



कड़वाहट से शुरु गरम मीठी चाय की चुस्की पर खत्म

शीत सत्र का समापन

एजेंसी | नई दिल्ली

बिहार के चुनाव नतीजों के बाद सत्तापक्ष के उत्साह व विपक्ष को लगे झटकों के माहौल में शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र आखिर में दोनों पक्षों के एक साथ हल्के फुल्के माहौल में कड़वाहट के बजाय मीठी चाय पीने के साथ समाप्त हुआ। पूरे सत्र में सरकार व विपक्ष ने एक दूसरे जमकर प्रहार किए और सहयोग के साथ विरोध में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा हुई और सरकार का अहम कामकाज भी हुआ। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन का यह पहला सत्र था और उन्होंने भी सदन का सफल संचालन किया।

राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर किए तीखे हमले कई अहम विधेयक पारित

संसदीय कामकाज

सत्र के दौरान 300 तारांकित प्रश्न स्वीकार किए गए, जिनमें से 72 का मौखिक उत्तर दिया गया। इसके अलावा 3,449 अतारांकित प्रश्न स्वीकार हुए। शून्यकाल में 408 तात्कालिक मुद्दे उठाए गए और नियम 377 के तहत 372 मामले लिए गए। इस तरह, शीतकालीन सत्र ने जहां कई अहम फैसलों की नींव रखी, वहीं राजनीतिक बहसों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गर्माहट भी बनाए रखी।

विपक्ष आलोचक के साथ रचनात्मक भी दिखा और सरकार अड़ियल के साथ सकारात्मक

सत्र की शुरुआत सरकार की तरफ से वंदेमातरम के 150 साल पर खास बहस और एसआईआर पर विपक्ष की चर्चा की मांग पर टकराव से शुरू हुआ था। बिहार के चुनाव नतीजे और बंगाल के आने वाले चुनावों को लेकर राजनीति भी जमकर हुई। वंदे मातरम पर बहस में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और मनरेगा की जगह लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर महात्मा गांधी को लेकर भी राजनीति हुई। दो बड़ी बहसों और दो बड़े विधेयकों ने सत्र को सार्थक बनाया। विपक्ष आलोचक के साथ रचनात्मक भी दिखा और सरकार अड़ियल के साथ सकारात्मक रही।

DBD

दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिसांसिबिलिटी है



पारित हुए आठ अहम विधेयक

इस सत्र में कुल आठ विधेयक पारित किए गए, जिनमें अनुपूरक अनुदान मांगें (2025-26) भी शामिल हैं। इनमें प्रमुख हैं: ग्रामीण भारत में 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाला वीबी-जी राम-जी विधेयक; नागरिक परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देने वाला शांति विधेयक; बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने वाला विधेयक, जिससे बीमा कवरज बढ़ने, प्रीमियम घटने और रोजगार सृजन की संभावना है; सबका बीमा सबकी रक्षा (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने मंजूरी दी; पुराने और अप्रासंगिक 65 संशोधन कानूनों और छह मूल कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक; साथ ही मणिपुर जीएसटी संशोधन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण से जुड़े अन्य विधेयक। उच्च शिक्षा से जुड़े विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया। इसका उद्देश्य एक उच्च शिक्षा आयोग और तीन अलग-अलग परिषदों की स्थापना करना है। वहीं, बाजार प्रतिभूति संहिता से जुड़ा एक विधेयक पेश कर स्थायी समिति को भेजा गया।

मोदी, राजनाथ और प्रियंका गांधी के बीच चाय पर चर्चा

बीते कुछ सालों में अधिकांश सत्र ऐसे रहे जिनकी समाप्ति बेहद कड़वाहट भी रहती थी, लेकिन इस बार यह सर्द माहौल में सरकार व समूचे विपक्ष के बीच लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में मीठी चाय की चुस्कियों के साथ समाप्त हुआ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी राजनाथ सिंह के साथ बैठी थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा और आपने संसदीय क्षेत्र वायनाड को लेकर चर्चा भी की। चाय के दौरान कई बार टहाके भी लगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी के विदेश में होने और उप नेता गौरव गोगोई के सदन में न होने से लोकसभा अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी को अन्य विपक्षी नेताओं के साथ चाय बैठक के लिए आमंत्रित किया था।

राहत आधी, संकट बाकी

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र के पूर्व खेल एवं युवा कार्य मंत्री माणिकराव कोकाटे को धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में दो साल की सजा के खिलाफ दायर अपील पर शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने सुनवाई के बाद एक लाख रुपये के मुचलके और श्योरिटी पर उन्हें जमानत दे दी। हालांकि हाई कोर्ट ने नासिक कोर्ट के फैसले पर स्थगन (स्टे) नहीं लगाया। इसका अर्थ है कि कोकाटे इस मामले में दोषी बने रहेंगे। उनकी विधायकी पर अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान एनसीपी (अजित पवार गुट) के विधायक माणिकराव कोकाटे की ओर से उनके वकीलों ने बचाव में दलीलें पेश कीं। वकीलों ने कहा कि जिस 25 एकड़ जमीन का उल्लेख किया जा रहा है, वह कोकाटे के पिता की थी। इस पर हाई कोर्ट ने तीखे सवाल उठाते हुए पूछा कि इतनी बड़ी जमीन की जानकारी हलफनामे में क्यों नहीं दी गई? क्या इसे संपत्ति छिपाना नहीं माना जाएगा? अदालत ने यह भी सवाल किया कि हलफनामे में खेती से होने वाली आय और जमीन का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आवेदन और हलफनामे में स्पष्ट विरोधाभास है।

पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को 1 लाख रुपये के श्योरिटी बॉन्ड पर मिली जमानत गिरफ्तारी टली लेकिन सजा पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया मना

हाई कोर्ट में बचाव पक्ष की दलीलें

वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने कहा कि कोकाटे को फॉर्जरी के मामले में दोषी ठहराया गया है, जबकि यह फॉर्जरी का मामला ही नहीं है। दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर स्वयं कोकाटे के हैं। कोई व्यक्ति अपने ही हस्ताक्षर की फॉर्जरी कैसे कर सकता है? उन्होंने कहा कि जानकारी भले ही गलत हो, लेकिन मात्र गलत जानकारी देना फॉर्जरी नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 463 के तहत दोषी ठहराया गया है, जो कानून उचित नहीं है।



सरकारी पक्ष का विरोध

सरकारी वकील ने बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि 1994 में हलफनामे में संपत्ति के खुलासे से संबंधित नियम जोड़ा गया था। ऐसे में केवल 1989 के आवेदन के आधार पर मामले को मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि निचली अदालत में गलत जानकारी और झूठे बयान देकर जमानत हासिल की गई थी। इस पर जस्टिस लड्डा ने सवाल किया कि उस समय इस पर क्या कार्रवाई की गई थी? सुनवाई के दौरान उस समय असहज स्थिति उत्पन्न हो गई, जब सरकारी वकील राज्य सरकार का स्पष्ट रुख अदालत के सामने नहीं रख पाए। इस बात को लेकर भ्रम बना रहा कि सरकार याचिका का विरोध कर रही है या नहीं।

कोकाटे को दो साल की सजा, मंत्री पद भी गया

गौरतलब है कि माणिकराव कोकाटे को नासिक की सत्र अदालत ने 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया था। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सजा को सत्र अदालत ने बरकरार रखा था। कोकाटे पर आरोप है कि उन्होंने नासिक के पॉश इलाके कॉलेज रोड स्थित 'निर्माण व्यू' अपार्टमेंट में 1989 से 1994 के बीच चार सरकारी प्लैट हासिल करने के लिए खुद को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का बताया था। कोकाटे की ओर से एडवोकेट अनिकेत निकम और वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने जस्टिस आर.एन. लड्डा की पीठ के समक्ष पक्ष रखा। वकीलों ने दलील दी कि 1989 में आवेदन के समय कोकाटे की आय पात्रता सीमा (33 हजार रुपये) के भीतर थी। आवेदन 11 सितंबर 1989 को किया गया था और उसका विधिवत सत्यापन भी हुआ था। वकीलों ने कहा कि भले ही 1993-94 में आय बढ़कर 34 हजार रुपये से अधिक हो गई हो, लेकिन पात्रता का निर्धारण आवेदन की तारीख के आधार पर किया जाना चाहिए।

DBD माणिकराव कोकाटे के MLA पॉइंट स्टेट्स का क्या होगा?

हाई कोर्ट ने माणिकराव कोकाटे की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया है। इस वजह से माणिकराव कोकाटे का MLA स्टेट्स खतरे में है। लेकिन क्या माणिकराव कोकाटे का MLA स्टेट्स बना रहेगा? कोर्ट ने इसे जरूरी बताया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा के स्पीकर को माणिकराव कोकाटे के MLA स्टेट्स के बारे में फ़ैसला लेना चाहिए।

बीएमसी चुनाव में 'आप' की एंट्री

सभी 227 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी 'आप'

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

आम आदमी पार्टी (AAP) ने बीएमसी चुनाव 2026 को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि पार्टी मुंबई की सभी 227 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया जाएगा।



गठबंधन राजनीति से दूरी

AAP नेता प्रीति शर्मा मेनन ने कहा कि मुंबई की मौजूदा बहाली के लिए पारंपरिक राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। पार्टी का मानना है कि अब मुंबई को एक ईमानदार और जवाबदेह विकल्प की जरूरत है, जो बिना समझौते के जनता के मुद्दों पर काम करे।

बीएमसी के कामकाज पर सवाल

पार्टी ने कहा कि 74,447 करोड़ रुपये के बजट वाली बीएमसी के बावजूद मुंबईकरों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। बदहाल सड़कें, गंदगी, कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं और गिरती शिक्षा व्यवस्था पर AAP ने गंभीर सवाल उठाए हैं। AAP का आरोप है कि बीएमसी स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है और BEST बस सेवा कमजोर की जा रही है। कचरा प्रबंधन व्यवस्था फेल है, पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है और वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हो गया है।

धारावी परियोजना और FD पर चिंता

पार्टी ने धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर बड़े भूमि घोटाले का आरोप लगाया है। AAP का कहना है कि बीएमसी पिछले चार वर्षों से बिना चुने हुए जनप्रतिनिधियों के चल रही है और निगम की 90 हजार करोड़ रुपये की एफडी घटकर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। पार्टी ने दिल्ली और पंजाब का उदाहरण देते हुए दावा किया कि बिना भ्रष्टाचार के शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली जैसे क्षेत्रों में सुधार संभव है।

ब्रीफ न्यूज़

ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

नई दिल्ली। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर सज़ान लेने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं और शिकायत पर आम बहने से इनकार करने के फैसले की अपील की मांग की है।

देशमुख हत्याकांड : सुनवाई 23 तक टली

बीड। संतोष देशमुख हत्याकांड में आरोप तय करने की प्रक्रिया फिर टल गई। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की विशेष अदालत ने अब सुनवाई 23 दिसंबर के लिए निर्धारित की है। आरोप तय होने के बाद ही मुकदमे की आधिकारिक सुनवाई शुरू होती है। अदालत ने यह निर्णय इसलिए लिया, क्योंकि बचाव पक्ष ने कहा कि अभियोजन ने अब तक वह साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं, जिन पर वह भरोसा कर रहा है। इसमें कथित वीडियो फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल हैं। बचाव पक्ष ने विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम की नियुक्ति पर भी आपत्ति जताई। आरोपियों ने दावा किया कि भाजपा सांसद होने के नाते उनकी नियुक्ति एक भाजपा विधायक की सिफारिश पर हुई, जिससे राजनीतिक पक्षपात की आशंका पैदा होती है।

बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर

उम्मीदवारों के ऐलान से पहले बनाई 20 सदस्यीय टीम डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई में बीएमसी चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख दल चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। महायुति में शामिल दलों की लगातार बैठकें हो रही हैं, वहीं भाजपा ने भी महानगरपालिका चुनाव को लेकर कमर कस ली है।

भाजपा ने गठित की चुनाव समिति

बीएमसी चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने एक विशेष समिति का गठन किया है। मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साठम के नेतृत्व में बनी इस समिति में केंद्र और राज्य स्तर के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। पार्टी का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को समय रहते पूरा करना है। चुनाव समिति में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावकर और कैबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा जैसे वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है।

मोहल्ले में घुसा तेंदुआ

डीबीडी संवाददाता | भाईदर ठाणे जिले के भायंदर शहर में शुक्रवार तड़के उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेंदुआ भटककर घनी आबादी वाले आवासीय इलाके में पहुंच गया। भायंदर पूर्व के तलाव मार्ग क्षेत्र में तेंदुए के हमले में चार लोग घायल हो गए, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल बन गया।

राहगीरों और निवासियों पर हमला अधिकारियों के अनुसार, तेंदुए ने पहले सड़क पर चल रहे कुछ राहगीरों पर हमला किया और बाद में 'पारिजात' नामक इमारत में घुस गया। वहां उसने कुछ निवासियों को भी घायल कर दिया। तेंदुआ कुछ समय के लिए इमारत के एक कमरे में छिपा रहा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उसे संकरे रास्ते और सीढ़ियों से गुजरते देखा गया।

घायलों का इलाज, तेंदुआ का पुनर्वास घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फंसे हुए तेंदुए को बोरीवली स्थित एएसजीएनपी के 'तेंदुआ बचाव केंद्र' ले जाया जाएगा। इस बीच, मानव-वन्डजीव संरक्षक पवन शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था आरएडब्ल्यूडब्ल्यू की टीम हालात पर नज़र बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए तैयार है।

रिपोर्ट दो-तिहाई यात्राएं दिल्ली, बंगलुरु और मुंबई से शुरू हुईं

मिलेनियल्स : 1981 से 1996 के बीच जन्मी पीढ़ी

एजेंसी | नई दिल्ली इस साल भारत से विदेश घूमने जाने वालों में सर्वाधिक मिलेनियल्स और जेन जी रहे। यह बात हालिया रिपोर्ट में सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार देश से 10 में से नौ विदेश यात्राएं इन्हीं दोनों पीढ़ियों के नाम रही। वर्ष 1981-1996 के बीच जन्मी पीढ़ी को मिलेनियल्स जबकि वर्ष 1997-2012 के बीच जन्मे लोगों को जेन जी कहा जाता है। यात्रा एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी मंच 'नियो' द्वारा जारी वार्षिक यात्रा रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे युवा, डिजिटल-फ्रंट और अनुभव-केंद्रित भारतीय कैसे बेहतर योजना, अकेले यात्रा और लागत-सचेत निर्णय के माध्यम से वैश्विक यात्रा प्रवृत्तियों को नया रूप दे रहे हैं।

नवंबर में 64 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर फेल

जांच में 200 से ज्यादा दवा नमूने घटिया डीबीडी संवाददाता | मुंबई

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि नवंबर महीने की जांच में केंद्रीय दवा प्रयोगशालाओं ने 64 दवा नमूनों को मानक गुणवत्ता का नहीं (एनएसक्यू) पाया है। इसके अलावा, राज्य दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 141 दवा नमूनों को भी एनएसक्यू श्रेणी में रखा है। मंत्रालय के अनुसार, यह जांच नियमित नियामक निगरानी के तहत की जाती है।

केंद्र और राज्य की प्रयोगशालाओं में हुई जांच

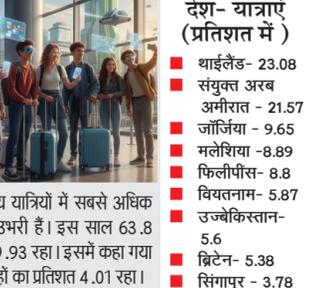
स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया कि नवंबर 2025 में केंद्रीय दवा प्रयोगशालाओं ने 64 और राज्य प्रयोगशालाओं ने 141 दवा नमूनों को मानकों पर खरा नहीं पाया। एनएसक्यू दवाएं वे होती हैं, जो किसी एक या एक से अधिक गुणवत्ता मानकों पर असफल पाई जाती हैं।

देश- यात्राएं (प्रतिशत में)

- थाईलैंड - 23.08
- संयुक्त अरब अमीरात - 21.57
- जाँजिया - 9.65
- मलेशिया - 8.89
- फिलीपींस - 8.8
- वियतनाम - 5.87
- उज्बेकिस्तान - 5.6
- ब्रिटेन - 5.38
- सिंगापुर - 3.78

अकेले घूमने वाले ज्यादा

रिपोर्ट के अनुसार, जेन जी और मिलेनियल्स ने 10 में से 9 अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कीं। इनमें से दो-तिहाई यात्राएं दिल्ली, बंगलुरु और मुंबई से शुरू हुईं, जो भारत के प्रमुख महानगरों के विदेश यात्रा पर मजबूत प्रभाव को दर्शाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय यात्रियों में सबसे अधिक पसंदीदा एकल यात्रा रही, जो एक विकल्प के तौर पर उभरी है। इस साल 63.8 प्रतिशत लोगों ने एकल यात्रा की। युगल यात्रा का प्रतिशत 19.93 रहा। इसमें कहा गया है कि इसके बाद परिवारों की यात्रा का प्रतिशत 12.26 एवं समूहों का प्रतिशत 4.01 रहा।



बागियों पर लगेगी लगाम

शिवसेना लाई 'स्पेशल मैनिफेस्टो'

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (टीएमसी) चुनाव में संभावित बागियों की 'बगावत' रोकने के लिए शिवसेना ने सख्त कदम उठाया है। पार्टी ने नगर निगम चुनाव में इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन पत्र में एक विशेष घोषणा-पत्र (स्पेशल मैनिफेस्टो) जोड़ दिया है। इसके तहत उम्मीदवारों को पार्टी के फैसले और नेतृत्व के आदेश को मानने की लिखित प्रतिबद्धता देनी होगी। शिवसेना के इस नए आवेदन फॉर्म में उम्मीदवारों से यह वादा लिया जा रहा है कि वे पार्टी द्वारा तय किए गए उम्मीदवार को ईमानदारी से जिताने के लिए काम करेंगे और किसी भी



स्थिति में बगावत या विरोध नहीं करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, आने वाले चुनाव में बागियों को रोकने के लिए इस विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

आपराधिक मामलों का भी खुलासा जरूरी

आवेदन पत्र की खास बात यह है कि इसमें उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी दर्ज करने का भी प्रावधान किया गया है। पार्टी का उद्देश्य साफ है कि नगर निगम चुनाव में दाम्नी छवि वाले उम्मीदवारों से दूरी बनाई जाए और संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखा जाए। घोषणा-पत्र में उम्मीदवार से यह लिखवाया जा रहा है कि वह शिवसेना के सिद्धांतों, अनुशासन और पार्टी हित को सर्वोपरि रखेगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि पार्टी द्वारा लिए गए निर्णयों को स्वीकार करते हुए अधिकृत उम्मीदवार को जिताने के लिए वह पूरी निष्ठा से कार्य करेगा। इस घोषणा पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए हैं।

नामांकन पर टीएमसी में चुनाव अधिकारी नदारद: राजन विचारे

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

राज्य चुनाव आयोग ने 15 दिसंबर को ठाणे नगर निगम चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक नामांकन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बावजूद नगर निगम द्वारा नियुक्त चुनाव निर्णय अधिकारी और संबंधित कर्मचारी चुनाव में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति सामने आई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता और पूर्व सांसद



राजन विचारे ने इस गंभीर मुद्दे की ओर ठाणे नगर निगम आयुक्त सौरभ राव का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के लिए पहले से ही सीमित समय है, ऐसे में चुनाव कार्यालय में अधिकारियों की अनुपस्थिति से उम्मीदवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नोटिस जारी, लेकिन व्यवस्था नदारद

राजन विचारे के अनुसार, घोषित आदेश के तहत ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 17 दिसंबर 2025 को एक नोटिस प्रकाशित किया था। इसमें वाई क्रमांक 01 से 33 के लिए चुनाव निर्णय अधिकारी के कार्यालय का पता, संबंधित अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर जारी किए गए थे। हालांकि, वास्तविकता यह है कि बताए गए पते पर न तो कोई अधिकारी मौजूद है और न ही चुनाव से संबंधित कोई व्यवस्था या सिस्टम सक्रिय दिखाई दे रहा है।

पारदर्शी और नियोजित चुनाव की मांग

पूर्व सांसद विचारे ने कहा कि चार दिन के भीतर नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन संबंधित अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी और उम्मीदवारों की समस्याओं का समाधान कहां होगा, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने आयुक्त को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि ठाणे नगर निगम चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी, सुव्यवस्थित और नियोजित तरीके से लागू किया जाए, ताकि उम्मीदवारों और मतदाताओं का भरोसा बना रहे।

प्रत्याशियों के चयन पूर्व एनसीपी एसपी की प्रचार रैली



डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (टीएमसी) चुनाव के लिए अब तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। फिलहाल इंटरन्यू सेशन जारी है। इसके बावजूद, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-शरद चंद्र पवार पार्टी ने कलवा में सक्रिय कैम्पेन रैलियों की शुरुआत कर दी है। इन रैलियों में उम्मीदवार बनने की इच्छा रखने वाले नेता अपने पक्के इरादों का इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जिस किसी को भी नामिनेशन मिलेगा, वे 'गद्दरों' को चुनाव में परास्त करेंगे।

एनसीपी ने किया सक्रिय कैम्पेन, नेताओं की मौजूदगी में बढ़ा उत्साह

ठाणे म्युनिसिपल चुनाव से पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने डॉ. जितेंद्र आह्लाड के मार्गदर्शन में, जिला अध्यक्ष मनोज प्रधान के नेतृत्व और रीता आह्लाड की मौजूदगी में अपने अभियान की जिम्मेदारी संभाली है। गुरुवार को कलवा के वाई नंबर 23 और 24 में पार्टी की तरफ से रैलियां आयोजित की गईं, जिनमें बिगुल बजाकर जनता को जागरूक किया गया और पार्टी के प्रत्याशियों का उत्साहवर्धन किया गया। कलवा में गांव के देवता के दर्शन के साथ शुरु हुई रैली शाम को विटावा में आयोजित की गई। इस पार्टी में चार सौ से अधिक उम्मीदवारों ने अपनी एप्लीकेशन जमा की है। सभी उम्मीदवारों ने रैली में हिस्सा लेकर स्पष्ट किया कि नामिनेशन चाहे किसी को भी मिले, वे चुनाव में जनता के विश्वास को तोड़ने वालों को हराकर पार्टी और जनता के हितों में काम करेंगे।

अवैध इमारतों से जूझता उल्हासनगर

डी.पी.प्लान को नजरअंदाज कर उल्हासनगर में हो रहा है बहुमंजिला इमारतों का निर्माण

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

उल्हासनगर शहर एक ओर जहां वर्षों से 855 अवैध इमारतों की समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर बिल्डरों और संबंधित अधिकारियों की कथित मिलीभगत से नियमों को दरकिनार कर नई इमारतों का निर्माण लगातार जारी है। हालात ऐसे हैं कि बिना वैधानिक और कानूनी स्थिति की जांच किए



नागरिक घर खरीद रहे हैं, जिससे शहर में अवैध निर्माण का इतिहास खुद को दोहराता नजर आ रहा है।

कार्रवाई न होने से नागरिकों में नाराजगी

नरेश चावला ने बताया कि वे जून माह से ही उल्हासनगर महानगरपालिका और संबंधित विभागों को लगातार पत्राचार कर भारी अनियमितताओं की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 18 दिसंबर 2025 को कोकण भवन स्थित विभागीय आयुक्त कार्यालय ने नगररचना अधिकारी को फटकार लगाते हुए जांच कर उचित कार्रवाई के आदेश दिए थे, इसके बावजूद मनापा प्रशासन की चुप्पी से नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। अवैध निर्माण के कारण सड़क संकरी हो गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पुनः निरीक्षण के निर्देश, कार्रवाई की प्रतीक्षा

इस मामले में अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस ने नगररचना विभाग के अधिकारियों को स्थल का पुनः निरीक्षण (स्थलपहानी), माप-जोख (मोजणी) करने, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। नागरिकों की मांग है कि सड़क में बाधा बने अवैध हिस्से को तत्काल तोड़ा जाए, ताकि आम लोगों के आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो।

52वां बळीराम कबड्डी महोत्सव का समापन



डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बळीराम क्रीडा मंडल की ओर से आयोजित 52वां कबड्डी महोत्सव स्थानीय 'ए' गुट टीमों के मुकाबलों के साथ भव्य और रंगीन रूप में संपन्न हुआ। 18 दिसंबर 2025 को महोत्सव का अंतिम दिन आयोजित किया गया। इस महोत्सव ने कबड्डी प्रेमियों को रोमांचक और उत्साही अनुभव देते हुए खिलाड़ियों में खेल भावना की जागरूकता बढ़ाई।

अंतिम मुकाबले में जय भारत क्रीडा मंडल की जीत

अंतिम मुकाबला विजय क्लब और जय भारत क्रीडा मंडल के बीच खेला गया। मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक और अनुशासित खेल प्रस्तुत किया। विजय क्लब ने शुरुआत में बल्ले बराने की कोशिश की, लेकिन जय भारत क्रीडा मंडल की मजबूत डिफेंस ने मुकाबले को संतुलित रखा। मध्यांतर के बाद

जय भारत क्रीडा मंडल ने अपने अनुभव के दम पर खेल पर नियंत्रण हासिल किया। उनके खिलाड़ियों ने सटीक पकड़, संयमित खेल और जोरदार चढ़ाई के जरिए अंक बढ़ाए। अंतिम कुछ मिनटों में विजय क्लब ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन निर्णायक क्षण में जय भारत क्रीडा मंडल ने संयम बनाए रखते हुए बढ़त कायम रखी।

अजित गुट महिला नेता का एनसीपी एसपी में प्रवेश

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे मनपा क्षेत्र के मुंब्रा में एनसीपी-शरद चंद्र पवार पार्टी को अजित पवार गुप से बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। डॉ. जितेंद्र आह्लाड की मौजूदगी में अजित पवार गुप की ठाणे शहर की महिला वर्किंग प्रेसिडेंट मनीषा भगत आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एनसीपी-शरदचंद्र पवार पार्टी में शामिल हो गईं। ठाणे जिला अध्यक्ष मनोज प्रधान ने उनका पार्टी में स्वागत किया और उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं। ठाणे एनसीपी के बयान के अनुसार, मनीषा भगत 2023 में अजित पवार गुप में शामिल हुई थीं और वर्तमान में वे उस गुप की ठाणे महिला वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही थीं। उन्होंने आज शरद पवार की विचारधारा और डॉ. जितेंद्र आह्लाड की लीडरशिप को स्वीकार करते हुए एनसीपी में शामिल होने का निर्णय लिया। मनीषा भगत ने कहा कि कुछ लोग विकास कार्यों को केवल राजनीति के नजरिए से देखते हैं, जबकि उनका उद्देश्य विकास की राह पर काम करना है। यही कारण है कि उन्होंने एनसीपी-शरद चंद्र पवार पार्टी में शामिल होने का फैसला किया।



हंगामा करने वाले तीन युवक-युवतियों को खडकपाड़ा पुलिस ने हिरासत में लिया

डीबीडी संवाददाता | कल्याण

कल्याण खडकपाड़ा पुलिस ने 19 तारीख को दोपहर लगभग एक से डेढ़ बजे के बीच निक्की नगर चौक के पास हंगामा करने और भीड़ जुटाने वाले तीन लोगों को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों में शुभम आशा बर्वे (22 वर्ष, व्यवसाय: विद्यार्थी, निवासी रूम नंबर 001, 'बी विंग', न्यू गंगा यमुना सोसायटी, आग्रा रोड, लालचौकी के पास, मोहिंदर सिंह हायरस्कूल, कल्याण) तथा उनकी दो मैत्रिणी वैष्णवी अवसरकर और तन्मयी खांडेकर शामिल हैं। घटना की



सूचना मिलते ही खडकपाड़ा पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों को सुरक्षित रूप से हिरासत में लेकर थाने ले गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रारंभिक पूछताछ और आगे की जांच

पुलिस ने बताया कि आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ जारी है और मामले की पूरी छानबीन के लिए आगे की कार्यवाही की जा रही है। जांच के दौरान सभी संबंधित पक्षों से जानकारी जुटाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

नवी मुंबई हवाई अड्डे के नामकरण में सरकार जानबूझकर कर रही देरी: सपकाल

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिवंगत डी बी पाटिल के नाम पर रखने की मांग दोहराई है। उन्होंने भाजपा नीत राज्य सरकार पर इस मुद्दे पर जानबूझकर निर्णय में देरी करने का आरोप लगाया। सपकाल ने कहा कि क्षेत्र की जनता की प्रबल भावना है कि हवाई अड्डे को पाटिल के नाम से ही जाना जाए। मॉडिया से बातचीत में सपकाल ने कहा कि नवी मुंबई के लोगों ने विकास के लिए अपनी जमीन



दी और डी बी पाटिल ने भूमिपुत्रों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि 12.5 प्रतिशत भूमि मुआवजा योजना पाटिल के आंदोलन की ही देन है। सपकाल के मुताबिक, पाटिल का नवी मुंबई, जेएनपीटी और हवाई अड्डे के विकास में योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

प्रदर्शन में शामिल होगी कांग्रेस

सपकाल ने बताया कि कांग्रेस 22 दिसंबर को स्थानीय संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शन में भाग लेगी और किसी भी अन्य नाम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे को 'पनपम एयरपोर्ट' कहे जाने और चारदीवारी पर उसी नाम के अक्षर लिखे जाने से आशंका है कि इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था और 25 दिसंबर से इसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने वाला है।

अवैध पोस्टरों पर मनपा का एक्शन

बिना अनुमति के पोस्टर और बैनर लगाए तो दर्ज होगा मामला



पोस्टर और बैनर हटाए गए हैं। मनपा आयुक्त सौरभ राव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब बिना अनुमति किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत विज्ञापन के पोस्टर, बैनर या होर्डिंग्स लगाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया जाएगा।

जोन-वार टीमों को सख्त निर्देश

आचार संहिता अवधि के दौरान अतिक्रमण विभाग और मनपा की जोन-वार टीमों के आपसी समन्वय से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी क्षेत्र में अवैध प्रचार सामग्री दोबारा न लगे। आयुक्त ने बताया कि प्रमुख सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक दीवारों, फ्लाईओवर, बिजली के खंभों, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से पोस्टर-बैनर लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एक ही ऑपरेशन में तीन जानलेवा ब्रेन समस्याओं का सफल इलाज

न्यू एरा अस्पताल में 54 वर्षीय महिला को मिली नई जिंदगी

डीबीडी संवाददाता | नवी मुंबई

नवी मुंबई स्थित न्यू एरा अस्पताल के डॉक्टरों ने एक साथ तीन जानलेवा ब्रेन समस्याओं से जूझ रही 54 वर्षीय महिला की जान बचाकर चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। मरीज के दिमाग के दोनों ओर बड़े ब्रेन ट्यूमर थे, जबकि एक हिस्से में खून भी जमा हुआ था। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है और किसी भी क्षण जानलेवा साबित हो सकती थी। शुरुआती जांच में महिला के दिमाग में केवल एक ट्यूमर होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन विस्तृत जांच के दौरान दिमाग में खून जमा होने और दूसरी ओर एक और ट्यूमर की पुष्टि हुई। इससे मरीज की हालत और अधिक गंभीर हो गई। डॉक्टरों के अनुसार, इन तीनों में से कोई भी समस्या लकवा, दौरे या मृत्यु का कारण बन सकती थी। न्यू एरा अस्पताल के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉ.



सुनील कुट्टी और उनकी टीम ने एक ही सर्जरी में दोनों ब्रेन ट्यूमर और दिमाग में जमा खून को सफलतापूर्वक निकाल दिया। यह अत्यंत जटिल ऑपरेशन करीब पांच घंटे तक चला। सर्जरी के बाद मरीज पूरी तरह होश में रही और धीरे-धीरे चलने में भी सक्षम हो गईं। कोपरखेरोगे निवासी श्रीमती सुमन पोखरे पिछले करीब 15 दिनों से कमजोरी, संतुलन बिगड़ने और रोजमर्रा के कामों में परेशानी महसूस कर रही थीं। जांच में दिमाग पर अत्यधिक दबाव पाया गया, जिसके बाद उन्हें तत्काल आईसीयू में भर्ती कर दवाइयां दी गईं और आपात सर्जरी का निर्णय लिया गया।

तेज रिकवरी, तीसरे दिन मिली छुट्टी

सर्जरी के बाद मरीज की हालत तेजी से सुधरी। अगले दिन उन्हें आईसीयू से सामान्य कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। किसी भी तरह का नर्व डेमेज नहीं पाया गया और तीसरे दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मरीज ने इसे 'जिंदगी का दूसरा मौका' बताया। वही अस्पताल के वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ डॉ. माताप्रसाद बी. गुला ने कहा कि आधुनिक तकनीक, अनुभवी डॉक्टरों और टीमवर्क के चलते यह जटिल सर्जरी सफल हो सकी।

स्पेशल ट्रेनों की सेवाएं जारी रखने का निर्णय

डीबीडी संवाददाता | सोलापुर

सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सोलापुर डिवाजन से होकर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार, इन ट्रेनों के विस्तार से यात्रियों



को आने-जाने में सुविधा मिलेगी।

साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी

सोलापुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (01435) साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, जो पहले 30 दिसंबर 2025 तक हर मंगलवार चलनी थी, अब 24 फरवरी 2026 तक संचालित होगी। इसी तरह लोकमान्य तिलक टर्मिनस-सोलापुर (01436) साप्ताहिक स्पेशल, जो 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित थी, अब 25 फरवरी 2026 तक हर बुधवार चलेगी। इसके अलावा सोलापुर-अनाकापल्ली (01477) और अनाकापल्ली-सोलापुर (01478) साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों को भी जनवरी से फरवरी 2026 तक बढ़ाया गया है।

डेली स्पेशल ट्रेनों का विस्तार

31 दिसंबर 2025 तक रोजाना चलने वाली सोलापुर-दौंड (01461/01462) और सोलापुर-कलभुज (01465/01466) अनारक्षित डेली स्पेशल ट्रेनों को 28 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं पुणे/हडपसर-हरंगुला (01487) और हरंगुला-पुणे/हडपसर (01488) डेली स्पेशल ट्रेनों का संचालन जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन ट्रेनों के समय, संरचना और उद्घाटन में पूर्व घोषित बदलावों को छोड़कर कोई अन्य परिवर्तन नहीं होगा।

ठाणे-मुलुंड के बीच शुरू होगा नए रेलवे स्टेशन का रुका हुआ काम

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया आश्वासन

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

ठाणे और मुलुंड के बीच प्रस्तावित नए सबर्बन रेलवे स्टेशन का लंबे समय से रुका काम अब सीधे रेलवे द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से फोन पर बातचीत कर स्पष्ट किया कि रेलवे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी कार्य अपने खर्च पर तुरंत शुरू करेगा। इससे परियोजना को नई गति मिलने की उम्मीद है।



संसद में उठा मुद्दा, सांसदों का फॉलोअप

काम में देरी को लेकर शिवसेना ग्रुप लीडर सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे और सांसद नरेश म्हस्के लगातार रेल मंत्रालय से फॉलोअप कर रहे थे। डॉ. शिंदे ने संसद में यह मामला उठाया था, जबकि नरेश

म्हस्के ने रेलवे एडवाइजरी कमिटी की बैठक में भी इस पर ध्यान दिलाया। दोनों सांसदों ने रेलवे और मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी को देरी का प्रमुख कारण बताया।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बनाई उत्तर भारतीयों को साथ लाने की रणनीति



मुंबई। महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं के चुनावों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों को साथ लाने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। पार्टी की योजना के तहत मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण संबंधी सुविधाएं दिलाने पर जोर दिया जाएगा।

आरक्षण में जटिलताएं और योजना

मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय ओबीसी समाज को यहां ओबीसी का दर्जा मिलने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र के नियम और कानून इतने जटिल हैं कि उत्तर भारतीय ओबीसी होने के बावजूद उन्हें आरक्षण और अन्य लाभ नहीं मिल पाते। शिंदे गुरु ने इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उपमुख्यमंत्री शिंदे शनिवार को उत्तर भारतीय ओबीसी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक ठाणे जिले के मुलुंड चेकनाका स्थित होटल टिप टॉप प्लाजा सभागृह में आयोजित होगी। पार्टी नेता संजय निरुपम को बैठक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बैठक में शामिल होंगे प्रमुख सामाजिक प्रतिनिधि

बैठक में उत्तर भारतीय ओबीसी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें विशेष रूप से विश्वकर्मा, बिंद, गुप्ता, चौहान, यादव, पाल, चौरसिया, धोबी, मोर्य, पासी, पटेल (कुर्मी), पटवा, प्रजापति, नाई, राजभर, लोधी, माली और निषाद समाज के नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बैठक का उद्देश्य इन समुदायों के मुद्दों पर चर्चा करना और उन्हें आरक्षण सहित अन्य लाभ दिलाने के लिए रणनीति तय करना है।

किंगफिशर कर्मचारियों मिली को राहत

ईडी ने 311.67 करोड़ रुपए की राशि बहाल की, जल्द मिलेगा बकाया

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएएल) के पूर्व कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित बकाये दिलाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। ईडी की पहल पर 311.67 करोड़ रुपये की राशि की बहाली सुनिश्चित की गई है, जिसे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अपराध की आय के रूप में जब्त संपत्तियों से हासिल किया गया है। यह कदम आर्थिक अपराधों से प्रभावित पीड़ितों को न्याय दिलाने की नीति को मजबूती देता है।

डीआरटी के आदेश के बाद राशि जारी करने की प्रक्रिया



यह राशि वेनई स्थित डेव्हस रिक्वरी ट्रिब्यूनल-1 के रिक्वरी अधिकारी द्वारा 12 दिसंबर 2025 को पारित आदेश के बाद जारी की जा रही है। ट्रिब्यूनल ने उन शेयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि को जारी करने का निर्देश दिया था, जिन्हें पहले ईडी ने अटैच किया था और बाद में पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बहाल किया गया। अब यह राशि आधिकारिक परिसमापक को सौंपी जाएगी, जो इसे किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों में वितरित करेगा।

विजय माल्या प्रकरण में ईडी की सक्रिय भूमिका

ईडी की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज कई एफआईआर पर आधारित थी, जिनमें किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या और संबंधित संस्थाओं पर बैंक धोखाधड़ी और आपराधिक घड़पत्र के आरोप थे। जांच में लोन राशि के बड़े पैमाने पर डायवर्जन और दुरुपयोग का खुलासा हुआ, जिसके बाद ईडी ने विजय माल्या, यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड

सहित कई संबद्ध इकाइयों की संपत्तियों कुर्क कीं। उल्लेखनीय है कि विजय माल्या को 5 जनवरी 2019 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। ईडी अब तक 14,132 करोड़ रुपये की संपत्तियां एसबीआई को बहाल कर चुका है, जिससे कर्मचारियों के एक दशक से अधिक समय से लटक बकायों के भुगतान का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

सत्तारूढ़ और विपक्ष दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू

उद्भव ठाकरे आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं : दानव

रावसाहब का अंतिम चुनाव हो चुका है- अंबादास



डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई मनापा चुनाव की गहमागहमी के बीच सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता रावसाहब दानव ने शिवसेना (उद्भव) के पक्ष प्रमुख उद्भव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उनके लिए मुंबई मनापा का आखिरी चुनाव होगा। दानव के मुताबिक, चुनाव के बाद शिवसेना (उद्भव) के अधिकांश पदाधिकारी और कार्यकर्ता अन्य दलों में चले जाएंगे।

2017 के चुनाव को लेकर दावा

शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में रावसाहब दानव ने कहा कि वर्ष 2017 के मुंबई मनापा चुनाव के समय वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे और तब भाजपा-शिवसेना (अविभाजित) की युति सरकार थी। उन्होंने दावा किया कि अगर भाजपा चाहती तो उसी समय मुंबई मनापा पर कब्जा कर सकती थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार चलाने के संतुलन के लिए शिवसेना को मौका दिया था।

सोमैया का बड़ा बयान

इस बीच भाजपा के पूर्व सांसद किरिट सोमैया ने भी ठाकरे भाइयों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्भव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मराठी अस्मित के नाम पर अपने राजनीतिक अस्तित्व को लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 16 जनवरी को दोनों का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सोमैया के अनुसार, मुंबई समेत 29 मनापा चुनावों के नतीजे इसी दिन घोषित होंगे।

अंबादास दानव का पलटवार

रावसाहब दानव और भाजपा नेताओं के बयानों पर शिवसेना (उद्भव) के नेता अंबादास दानव ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रावसाहब 2024 के लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं और वही उनका अंतिम चुनाव था। अंबादास दानव ने कहा कि रावसाहब को शिवसेना (उद्भव) की चिंता करने के बजाय अपने राजनीतिक भविष्य पर ध्यान देना चाहिए।

नगर निकाय चुनाव

चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे : तटकरे

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी नेतृत्व 15 जनवरी को होने वाले 29 महानगर पालिकाओं के चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेगा। इस बैठक में महायुति गठबंधन की संयुक्त चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तटकरे ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्होंने शहरी इलाकों में राकांपा की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने



कहा कि इस संबंध में उपमुख्यमंत्री अजित पवार से भी परामर्श किया जाएगा, ताकि गठबंधन के भीतर बेहतर समन्वय के साथ चुनावी योजना को अंतिम रूप दिया जा सके।

सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत

राकांपा नेता ने कहा कि महायुति को मजबूत और एकजुट रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई नगर निकायों में भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है, जिसे आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की जा रही है।

हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि एक दर्शन है : सीएम फडणवीस

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मुंबई में कहा कि हिंदू धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका और दर्शन है। उन्होंने कहा, यह एक प्राचीन प्रणाली है जिसने हजारों सालों से हमारी संस्कृति को जीवित रखा है। भारतीय सभ्यता ही एकमात्र निरंतर सभ्यता है, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री यह वचन वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में संबोधन के दौरान दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारतीय सभ्यता पाषाण युग के दौरान भी विकसित थी। उन्होंने यह भी बताया कि समृद्ध राष्ट्र ही दुनिया का नेतृत्व करते हैं और भारत को खुद को एक समृद्ध देश के रूप में स्थापित करना चाहिए। फडणवीस ने कहा, रहम हमेशा से इन्होवर रहे हैं।

सातारा झग मामले में उपमुख्यमंत्री पर राजनीति न करने की चेतावनी

सातारा झग मामले में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम को जोड़ने संबंधी सवाल पर फडणवीस ने कहा कि यह जानबूझकर राजनीतिक कोशिश है, जो रूढ़ी तरह गलत और निंदनीय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक इस मामले में सामने आए किसी भी सबूत का एकनाथ शिंदे या उनके परिवार से कोई लेना-देना नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को गुमराह करना और ऐसे गंभीर मामलों में राजनीति करना उचित नहीं है।

जज पर रिश्वतखोरी का आरोप आवास की ली गई तलाशी

पक्ष में फैसला सुनाने के लिए मांगे 25 लाख

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने मुंबई के एक सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसीबी ने अदालत को सूचित किया है कि बांबे हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आरोपी न्यायाधीश के आवास पर तलाशी ली गई है और डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। यह मामला एक भूमि विवाद में अनुकूल फैसला सुनाने के बदले रिश्वत मांगने से जुड़ा है।

व्हाट्सएप कॉल है अहम सबूत

एसीबी ने बताया कि 18 नवंबर को बांबे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एजाजुद्दीन काजी को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी गई थी। जिसके बाद एसीबी ने 8 दिसंबर को जज एजाजुद्दीन काजी को अपने दफ्तर बुलाया और उनकी आवाज का नमूना लिया। इस नमूने का मिलान उस रिकॉर्डिंग से किया जाएगा जिसमें व्हाट्सएप कॉल पर मराठी में बातचीत हुई थी। इसलिए एसीबी आरोपी न्यायाधीश के आवाज के नमूनों सहित अन्य डिजिटल साक्ष्य एकत्र कर रही है।

25 लाख की डिमांड, रंगे हाथ वलक पकड़ाया



मामले की जड़ एक पुराने भूमि विवाद से जुड़ी है। आरोपी न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काजी की अदालत में वलक-सह-टाइपिस्ट के रूप में काम करने वाले चंद्रकांत वासुदेव को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। चंद्रकांत वासुदेव पर 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। एसीबी का दावा है कि कोर्ट वलक चंद्रकांत वासुदेव ने कथित तौर पर जज और अपने किए कुल 25 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाया और चंद्रकांत को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

बांबे हाईकोर्ट ने दी जांच की अनुमति

बता दें कि न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। बांबे हाईकोर्ट ने इस मामले में न्यायाधीश एजाजुद्दीन काजी के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी, जिसके बाद एसीबी ने उनके आवास की तलाशी ली। इस घटना को लेकर कानूनी गलियारों में हड़कंप मच गया है।

राज ठाकरे से मिले यूबीटी नेता अनिल परब

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के नेता अनिल परब ने शुक्रवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुंबई में उनके शिवतीर्थ निवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात मुंबई मनापा चुनावों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, मुंबई महानगरपालिका में यूबीटी और मनसे के बीच गठबंधन लागू हो चुका है और अब केवल अधिकृत घोषणा का इंतजार है। अनिल परब ने इससे पहले भी दो दिन पहले राज ठाकरे से मुलाकात की थी, जबकि दोनों पार्टियों के बीच पिछले कुछ दिनों से सीट बंटवारे और चुनाव रणनीति को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, आगले दो से तीन दिनों में इस गठबंधन की घोषणा हो सकती है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी या जॉइंट मीटिंग के जरिए की जाएगी।



पश्चिम रेलवे

निरस्तीकरण सूचना
निविदा सूचना सं.: BCT/25-26/272, दिनांक: 02/12/2025, डीओपी (खोलने की तिथि): 26/12/2025 — यह निविदा निविदा दस्तावेज में उचित होने के कारण निरस्त की जाती है।
0916
इस लाइक करें: [facebook.com/WesternRly](https://www.facebook.com/WesternRly)

पश्चिम रेलवे

स्वचालित कोच धुलाई संयंत्र (ACWP) की मरम्मत
Sr. CDO-ICD-BDTS निविदा सूचना सं.: M137-BDTS-ACWP, दिनांक: 15.12.2025 आमंत्रित करने हेतु। कार्य का नाम: कोचिंग डिपो बार्द में स्थित स्वचालित कोच धुलाई संयंत्र (ACWP) की एक बगैर की मरम्मत, साथ ही 05 वर्षों का समान वार्षिक रखरखाव एवं संचालन (CAMOC)। कार्य की अनुमानित लागत: 99,57,532.24/- (सब्सी करोड़ सहित)। ईमेल: 1,99,200/- निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 06.01.2026, 15:00 बजे तक अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे वेबसाइट देखें: www.ireps.gov.in
0906
इस लाइक करें: [facebook.com/WesternRly](https://www.facebook.com/WesternRly)

पश्चिम रेलवे

निविदा सूचना सं.: BCT/25-26/272, दिनांक: 02/12/2025, डीओपी (खोलने की तिथि): 26/12/2025 — यह निविदा निविदा दस्तावेज में उचित होने के कारण निरस्त की जाती है।
0916
इस लाइक करें: [facebook.com/WesternRly](https://www.facebook.com/WesternRly)

PUBLIC NOTICE

NOTICE hereby given public at large that, Mrs. Supriya Milind Chavan & Mr. Milind Damodar Chavan want to sale their Flat No. B/105, 1st Floor, ParagApartment, Jay Parag CHS Ltd., V.M. Shah Marg, Near Santok Talkies, Bhayander (W), Dist. Thane - 401101 to Ms. Mahima Ramvilas Yadav. The said Mrs. Supriya Milind Chavan & Mr. Milind Damodar Chavan had purchased the above said Flat from Mr. Hareesh Hiralal Shah @ Gandhi & Bhavin Hiralal Shah @ Gandhi and the said Mr. Hareesh Hiralal Shah @ Gandhi & Bhavin Hiralal Shah @ Gandhi had purchased the said flat from Pushpalata Ramesh Jain and Mrs. Pushpalata Ramesh Jain had purchased the said flat from builder M/s. Vraj Builder. If having any objection, claim by any one please contact on below mentioned address & Contact Number within 15 days from the publication of this notice, else it is considered that no one have any objection regarding the said flat sale/purchase. Sd/- Mr. VIVEK SINGH Advocate, High Court, Bombay Address: C-35/101, Heli, Sector-11, Mira Road (E), Dist. Thane - 401107. Mobile No. : 9769990888

पूर्व पत्नी के खिलाफ कुमार सानू की मानहानि याचिका

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रोक की मांग

कुमार सानू ने अपनी याचिका में रीता भट्टाचार्य के साथ-साथ गूगल, मेटा और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी प्रतिवादी बनाया है। अदालत से अनुरोध किया गया है कि गायक और उनके परिवार से जुड़ी कथित मानहानिकारक सामग्री के प्रसारण और प्रसार पर तत्काल रोक लगाई जाए।



डीबीडी संवाददाता | मुंबई

प्रसिद्ध गायक कुमार सानू ने अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट में 50 करोड़ रुपये की मानहानि याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भट्टाचार्य द्वारा दिए गए हालिया इंटरव्यू और प्रशंसक मीडिया टिप्पणियों से उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है।

इंटरव्यू और सोशल मीडिया टिप्पणियों पर आपत्ति

याचिका में कहा गया है कि सितंबर 2025 में यूट्यूब चैनलों 'फिल्म विंडो', 'वायरल भयानी' और 'सिद्धार्थ कन्नन' को दिए गए इंटरव्यू में भट्टाचार्य ने शादी के दौरान सानू के आचरण को लेकर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए। ये वीडियो और रील

सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुए। कुमार सानू का आरोप है कि इन वीडियो विलप्स को सामूहिक रूप से 15 लाख से अधिक बार देखा गया, जिससे उनकी सद्भावना, ईमानदारी और पेशेवर विश्वसनीयता पर अनुचित सवाल खड़े हुए।

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Executive Engineer, Central Mumbai Electrical Division, PWD, Worli Mumbai 400018
E-TENDER NOTICE NO 52/25-26 (Corrigendum)
Online E-Tenders in "B-1" form for the Mentioned works in Notice 52/25-26 ar invited by the Executive Engineer, Central Mumbai Elect. Division, PWD Worli Mumba Government of Maharashtra, Electronic Tenders Management System <http://mahatenders.gov.in> from Qualified contractors as per Quality-fying Criteria for this work.
Already Published

Tender Issue Date	Dt. 16.12.2025 at 17.30 hrs to 23.12.2025 at 17.30 hrs
Opening Date	Dt 26.12.2025 after 11.00 AM

Now Read as

Mentioned E-Tender Notice no 52/25-26 is Cancelled

No.EE/CMED/Tender/4315/2025
Date 15/12/2025

SD/-
(N.S.Sutrave)
Executive Engineer
Central Mumbai Elect.Div
PWD Worli Mumbai,

Copy - To notice board at Office of The Executive Engineer, Central Mumbai (Elect) Division, PWD Worli Mumbai
DGIPR-2025-26/4678

न्यूज ग्रीफ

जुमे की नमाज के बाद चले ईट-पत्थर, दो पक्षों में पथराव, एक महिला घायल फर्रुखाबाद। जिले के कमालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शेखपुर में जुमे की नमाज के बाद दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हो गया। घटना में ईट-पत्थर लगने से एक महिला घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव निवासी जावेद खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शेखपुर मेले के दौरान उसका अमन, आयन, रेहान, मुल्ला, फजल और फैजान से विवाद हो गया था। इसी संज्ञिक के चलते शुक्रवार को नमाज अदा कर लौटते समय आरोपितों ने अपने अन्य 7-8 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उस पर ईट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव की चपेट में आने से गांव की ही जुवेदा बेगम घायल हो गई। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी राजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पथराव के साक्ष्य मिले। ग्रामीणों ने आरोपितों को लेकर सपा विधायकों ने आरोप न किया जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोडीन कफ सिरप प्रकरण: पोस्टर और साइकिल लेकर सदन में पहुंचे सपाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कोडीन कफ सिरप प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सपा विधायक विरोध स्वरूप पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे, जबकि कुछ जनप्रतिनिधि साइकिल से विधान भवन परिसर में पहुंचे। प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप की कथित तस्करी को लेकर सपा विधायकों ने आरोप लगाया कि मामले में प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता है, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई से बच रही है। सपा विधायक मुकेश वर्मा के बाद विधायक बृजेश यादव भी पोस्टर पहनकर विधानसभा पहुंचे और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं वाराणसी से समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा साइकिल पर कफ सिरप की शीशी के कटआउट के साथ विधानसभा पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में बड़े स्तर पर संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले 'कालीन भैया' की चर्चा होती थी, अब 'कोडीन भैया' सामने आ गए हैं, लेकिन सरकार का बुलडोजर कहीं नजर नहीं आ रहा है।

शीतलहर के चलते इंटर तक के स्कूल दो दिन बंद

फर्रुखाबाद। जिले में भीषण शीत लहर और घने कोहरे को देखते हुए नर्सरी से इंटरमीडियट तक संचालित सभी स्कूलों में दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ सिंह ने बताया कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार परिषदीय, सहायता प्राप्त तथा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों में 19 और 20 दिसंबर को शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। हालांकि, विद्यालयों में तैनात शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को नियमित रूप से उपस्थित रहकर विभागीय एवं निर्वाचन संबंधी कार्यों का निर्वहन करना होगा।

गैंगरेप, हत्या के चार दरिंदों को आजीवन कारावास

प्रत्येक दोषियों पर 1.12 लाख रुपये का जुर्माना, एक बाल अपचारी की पत्रावली पर अलग से होगी सुनवाई

एजेंसी | संभल

उत्तर प्रदेश के संभल जनपद की गुन्नौर तहसील अंतर्गत थाना रजपुरा क्षेत्र में वर्ष 2018 में सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला को जिंदा जलाकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 1.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में शामिल एक बाल अपचारी की पत्रावली पृथक कर दी गई है, जिसका विचारण अलग से होगा। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (फॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी। न्यायालय ने अभियुक्त आराम सिंह, भोना उर्फ कुमरपाल, गुल्लू उर्फ जयवीर और महावीर को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 201, 302, 376 डी एवं 34 के तहत दोषी ठहराया। सजा सुनाए जाने के बाद सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।



झोपड़ी में बंद कर लगा दी थी आग

अभियोजन के अनुसार, थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित के पति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 13 जुलाई 2018 की रात उसकी अनुपस्थिति में गांव के ही चार लोगों ने उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के उजागर होने के भय से आरोपियों ने महिला को घर से कुछ दूरी पर स्थित एक मंदिर की झोपड़ी में बंद कर आग लगा दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जघन्य अपराधों के विरुद्ध सख्त संदेश देने वाला है। जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया था। चंडौसी कोर्ट में आज 19 दिसंबर के दौरान परिजनों के वकील ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की अपील की थी, हालांकि कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए चारों को ताउम्र कैद की सजा दी। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पीड़िता के परिवार को वह न्याय मिल गया जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे।

पिंजड़े में कैद गुलदार को लेकर वन नर्सरी पहुंचे ग्रामीण

एजेंसी | बिजनौर

बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के नजीबाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव धनसिनी में शुक्रवार को एक मादा गुलदार पिंजरे में कैद हो गई। यह एक माह के भीतर उसी गांव में पकड़ी गई तीसरी गुलदार है। सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने पिंजरे में गुलदार को कैद देखा, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और गुलदार को देखने के लिए भीड़ जुट गई। कुछ ग्रामीण पिंजरे के पास सेल्फी लेते भी नजर आए। मामले की जानकारी सामाजिक वानिकी विभाग को दी गई, लेकिन करीब एक घंटे तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद ग्रामीणों ने सुरक्षा को देखते हुए पिंजरे में बंद गुलदार को गांव के पास लाकर एक वाहन में लादा और स्वयं उसे जालपुर स्थित वन विभाग की नर्सरी तक पहुंचाया।

▶▶ माहभर के भीतर उसी क्षेत्र में पकड़ी गई तीसरी मादा गुलदार

लगातार खेत में लगाया जा रहा पिंजड़ा

इस दौरान पिंजरा वाहन पर चढ़ाते समय कुछ देर के लिए उसका दरवाजा खुल गया, जिससे मौके पर अफरा-ताफरी मच गई। हालांकि, गुलदार के थके होने के कारण वह बाहर नहीं निकली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों के अनुसार इससे पहले भी इसी खेत में लगाए गए पिंजरे में दो गुलदार पकड़े जा चुके हैं।



लखनऊ में छत पर खेल रही मासूम के सिर में लगी गोली

▶▶ सफल ऑपरेशन के बाद खतरे से बाहर

एजेंसी | लखनऊ



राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बस्तीली गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां घर की छत पर खेल रही तीन वर्षीय बच्ची के सिर में गोली लग गई। समय रहते उपचार मिलने से बच्ची की जान बच गई है और ऑपरेशन के बाद उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बस्तीली गांव निवासी रमेश की तीन वर्षीय पुत्री लक्ष्मी अपने दो भाइयों के साथ घर की छत पर बने टिन शेड के नीचे खेल रही थी। इसी दौरान अचानक तेज आवाज सुनाई दी और बच्ची लहलुहान होकर गिर पड़ी। परिजन तत्काल उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने घंटों उसे ऑपरेशन के बाद सिर में फंसे गोली के छर्रों को निकालकर उसकी जान बचाई।

कहां से चली गोली, स्थिति अस्पष्ट

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी गाजीपुर राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस यह जांच कर रही है कि गोली किस दिशा से आई और इसे किसने चलाया। आसपास के क्षेत्रों की गहनता से जांच की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विवेचना की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है।

शास्त्री पुल पर ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा

एजेंसी | प्रयागराज



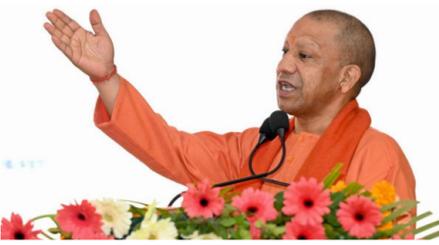
उप्र के प्रयागराज जिले में स्थित झूंसी थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात शास्त्री पुल पर ट्रक से दबकर दो युवकों की जान चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि हादसे में नगर के दारागंज थाना क्षेत्र के मोरी दारागंज निवासी विशाल मिश्रा 32 वर्ष पुत्र जय किशन मिश्र और उसके साथी अंकुर 35 वर्ष की मौत हुई है। डीसीपी ने बताया कि विकास उर्फ विशाल मिश्रा गुरुवार देर रात मोटरसाइकिल से अपने दोस्त अंकुर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस यह जांच कर रही है कि गोली किस दिशा से आई और इसे किसने चलाया। आसपास के क्षेत्रों की गहनता से जांच की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विवेचना की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है।

माफिया नेटवर्क से जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के तार : सीएम

▶▶ कोडीन कफ सिरप प्रकरण पर सीएम योगी का विपक्षी दल पर तीखा हमला

एजेंसी | लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सक्रिय माफिया तत्वों के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं और अब तक की जांच में पकड़े गए लोगों के तार भी सपा से जुड़े पाए गए हैं। शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधान भवन स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोडीन कफ सिरप प्रकरण की जांच जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और तथ्यों के सामने आने पर सच्चाई स्तः उजागर हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।



धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा

कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आक्रामक रुख पर मुख्यमंत्री योगी ने उर्दू शायर गालिब का शेर पढ़ते हुए तंज कसा— “उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा।” मुख्यमंत्री ने बताया कि शुक्रवार से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें सभी सदस्यों का स्वागत है। सत्र के दौरान ‘वंदे मातरम’ पर चर्चा प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती थी कि सत्र अधिक समय तक चले, लेकिन जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर इसे सीमित अवधि का रखा गया है। विधानसभा सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। एक विधायक के निधन के कारण शोक स्वरूप शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी, जबकि विधान परिषद में इस मुद्दे पर सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक तथा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी उपस्थित रहे।



ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने AI में किया निवेश

मिनिवेट एआई में हासिल की बहुमत हिस्सेदारी

एजेंसी | नई दिल्ली

नई दिल्ली। देश की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करते हुए एआई समाधान प्रदाता कंपनी मिनिवेट एआई में बहुमत हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है। कंपनी ने इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, हालांकि सौदे से जुड़े वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। यह अधिग्रहण नियामकीय और अन्य सामान्य शर्तों की पूर्ति के अधीन रहेगा। मिनिवेट एआई के संस्थापक आदित्य रचकोंडा ने इस साझेदारी को कंपनी के लिए अहम पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट के साथ सहयोग से उनके स्वामित्व वाले जेनरेटिव एआई समाधान— जैसे कैटलॉग वीडियोगेनरेशन और कन्वर्सेशनल सर्च—को देश के बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकेगा, जिससे ग्राहकों के लिए ऑनलाइन खरीदारी का अनुभव अधिक सहज और आकर्षक बनेगा।



दीर्घकालिक नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट) रवि अय्यर ने कहा कि यह अधिग्रहण एक रणनीतिक निवेश है, जिससे कंपनी की कोर जेनएआई क्षमताओं को उन्नत तकनीक और विशेष प्रतिभा के माध्यम से मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि वीडियो-फर्स्ट और विजुअल-फर्स्ट कॉमर्स जैसे उभरते रुझानों को देखते हुए यह निवेश ग्राहक जुड़ाव, कन्वर्जन और दीर्घकालिक नवाचार को बढ़ावा देगा।

150 मिलियन उत्पादों की हो रही बिक्री

उल्लेखनीय है कि फ्लिपकार्ट समूह देश की अग्रणी डिजिटल कॉमर्स कंपनियों में शामिल है। समूह के पोर्टफोलियो में फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट होलसेल, क्लियरट्रिप और सुपर.मनी जैसी कंपनियां शामिल हैं। वर्ष 2007 में स्थापित फ्लिपकार्ट आज 500 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और 1.4 मिलियन से ज्यादा विक्रेताओं के साथ 80 से अधिक श्रेणियों में 150 मिलियन से ज्यादा उत्पादों को पेशकश कर रहा है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.04 लाख करोड़ रुपए पार पहली छमाही में आई मजबूती आठ प्रतिशत का उछाल

नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक अप्रैल से 17 दिसंबर के बीच प्रत्यक्ष कर संग्रह आठ प्रतिशत की वृद्धि के साथ 17.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है। आयकर विभाग के अनुसार, कर संग्रह में इस बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में आई धीमी गति रही है। आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में कॉर्पोरेट कर से 8.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि गैर-कॉर्पोरेट कर से लगभग 8.47 लाख करोड़ रुपये का योगदान रहा। इसके अलावा, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से 40,195 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व अर्जित किया गया।

रिफंड में सालाना 14 फीसद की गिरावट

विभाग ने बताया कि रिफंड जारी करने में सालाना आधार पर करीब 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है और 17 दिसंबर तक कुल रिफंड राशि 2.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही। रिफंड को समायोजित करने से पहले सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 4.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 20.01 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य 25.20 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12.7 प्रतिशत अधिक है। वहीं, चालू वित्त वर्ष में एप्रैलटी से 78,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

डॉ बत्राज® ने लॉन्च किया एक्सओडर्मा स्किन ट्रीटमेंट

नई दिल्ली। भारत में आधुनिक होम्योपैथी के क्षेत्र में अग्रणी डॉ. बत्राज ने त्वचा पुनर्जीवन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए डॉ. बत्राज एक्सओडर्मा लॉन्च किया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला उपचार है, जो होम्योपैथी को आधुनिक स्किन एक्सोसोम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है। यह थैरेपी खासतौर पर एंटी-एजिंग और एंटी-पिग्मेंटेशन के लिए विकसित की गई है और नॉन-इंजेक्टेबल, नॉन-इनवेसिव तथा पूरी तरह दर्दरहित है। केवल तीन सत्रों में स्पष्ट परिणाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया यह



पुनर्जनन प्रक्रियाओं को सक्रिय करते हैं, जिससे केवल सतही नहीं बल्कि दीर्घकालिक और प्रभावी परिणाम मिलते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से त्वचा की बनावट, रंगत, कसाव और स्पष्टता में समय के साथ उल्लेखनीय सुधार देखा जाता है। लॉन्च के अवसर पर डॉ. बत्राज® हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक, ट्राइकोलॉजिस्ट और होम्योपैथिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट एवं एस्थेटिक्स में फेलोशिप धारक डॉ. अक्षय बत्रा ने कहा कि मरीजों को वास्तविक और सुरक्षित लाभ पहुंचाने वाला नवाचार ही उनकी प्राथमिकता है।

बीमा विधेयक से आसान हुआ जीवन बीमा: LIC सीईओ

नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक आर. दुरईस्वामी ने संसद में हाल ही में पारित बीमा विधेयक को बीमा क्षेत्र के लिए अहम मोड़ बताया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर बीमा पॉलिसियों को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाएगा तथा क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शुक्रवार को जारी बयान में एलआईसी प्रमुख ने कहा कि 'सबका बीमा, सबकी रक्षा' (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 का फोकस पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और नियामकीय ढांचे को सुदृढ़ करने पर है। उनके अनुसार, यह विधेयक पुरानी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी को मजबूत करता है, जिससे बीमा उद्योग की दीर्घकालिक वृद्धि को गति मिलेगी। दुरईस्वामी ने बताया कि संशोधित कानून बीमाकर्ताओं को अधिक परिचालन लचीलापन और नवाचार का अवसर प्रदान करेगा।

पार्थ जिंदल सीमेंट निर्माता संघ के नए अध्यक्ष

▶▶ डॉ. राघवपत सिंघानिया उपाध्यक्ष नियुक्त

मुंबई। भारत में सीमेंट निर्माताओं के शीर्ष संगठन सीमेंट निर्माता संघ (सीएमए) की 18 दिसंबर 2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पार्थ जिंदल को नया अध्यक्ष चुना गया। वहीं, जेके सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. राघवपत सिंघानिया ने उपाध्यक्ष का पदभार संभाला। जिंदल ने श्री सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीरज अखौरी का स्थान लिया। सीएमए सदस्यों ने सर्वसम्मति से दोनों नियुक्तियों का समर्थन करते हुए संघ के नेतृत्व पर विश्वास जताया।

नीतिगत वकालत और सतत विकास पर फोकस



राघवपत सिंघानिया अपने व्यापक उद्योग अनुभव के साथ अनुसंधान, नवाचार और सदस्य कंपनियों के बीच समन्वय को मजबूत करेंगे। दोनों नेताओं से अपेक्षा है कि उनके संयुक्त प्रयासों से सीएमए की भूमिका न केवल उद्योग हितों की रक्षा में बल्कि राष्ट्र निर्माण, अवसररचना विकास और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को सशक्त बनाने में और अधिक प्रभावी होगी।

अध्यक्ष के रूप में पार्थ जिंदल नीति निर्माताओं, नियामकों और अन्य हितधारकों के साथ सीएमए के नीतिगत एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। इसमें सतत विनिर्माण, डीकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा परिवर्तन और लॉजिस्टिक्स अनुकूलन पर विशेष जोर रहेगा। वहीं उपाध्यक्ष डॉ. राघवपत सिंघानिया अपने व्यापक उद्योग अनुभव के साथ अनुसंधान, नवाचार और सदस्य कंपनियों के बीच समन्वय को मजबूत करेंगे। दोनों नेताओं से अपेक्षा है कि उनके संयुक्त प्रयासों से सीएमए की भूमिका न केवल उद्योग हितों की रक्षा में बल्कि राष्ट्र निर्माण, अवसररचना विकास और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को सशक्त बनाने में और अधिक प्रभावी होगी।

सीएमए के इतिहास में पहली बार युवा जोड़ी

जिंदल एएसोसिएशन के अब तक के सबसे कम उम्र के निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं। उनसे पर युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि चुने गए हैं। पार्थ भारतीय सीमेंट उद्योग के सामने मौजूद चुनौतियों के समाधान के लिए नई ऊर्जा, नवोन्मेषी सोच और दूरदर्शी दृष्टिकोण लाने की उम्मीद जताई जा रही है।

रूस-यूक्रेन युद्ध तुरंत रोकने के लिए पुतिन हुए तैयार



मॉस्को। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर बड़ी टिप्पणी की है। पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए तुरंत तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक बड़ी शर्त रख दी है। पुतिन ने कहा कि अगर उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाए तो वह यूक्रेन से युद्ध रोकने को तैयार हैं। यूक्रेन के साथ शांतिवार्ता पर पुतिन ने कहा कि हालांकि अब तक, हमें वास्तव में ऐसी तत्परता यूक्रेन की तरफ से नहीं दिखती। लेकिन फिर भी हम कुछ संकेत देखते हैं। इनमें कीव शासन से भी संकेत शामिल हैं, कि वे किसी प्रकार की बातचीत में शामिल होने को तैयार हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा यही कहते रहे हैं। हम इस संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। इस दौरान पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए जा रहे शांति प्रयासों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस संघर्ष को खत्म करने के लिए बेहद गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एंकरिज में हमने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावों पर सहमति जताई और व्यावहारिक रूप से उन्हें मान लिया। इसलिए यह कहना कि हम किसी भी चीज को अस्वीकार कर रहे हैं पूरी तरह से गलत है। इसका कोई आधार नहीं है। मॉस्को में प्रारंभिक बैठकों में, हमें कुछ प्रस्ताव दिए गए और हमसे कुछ समझौते करने को कहा गया। जब मैं एंकरिज पहुंचा, मैंने कहा कि यह हमारे लिए आसान निर्णय नहीं हो।

सितारों की शामत

ईडी ने जब्त की क्रिकेटर्स और फिल्मी हस्तियों की संपत्तियां

एजेंसी | नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet की जांच में अब क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार के बाद सांसद का नाम भी शामिल हो गया है। इस मामले में आरोपियों की 7.93 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। अभी तक जांच एजेंसी ईडी द्वारा कुल 19 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है। सूत्रों का कहना है कि इस केस की जांच का दायरा, अब बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में कई दूसरे जाने-माने चेहरे ईडी की पृच्छाछ के दायरे में आ सकते हैं। इनमें क्रिकेटर्स के अलावा फिल्मी जगत के कई नाम शामिल होने की संभावना है। राजनीतिक दलों से जुड़ी कई हस्तियां भी ईडी के रडार पर हैं।

क्या है मामला?

ईडी की जांच में पता चला कि इन सेलिब्रिटीज ने जानबूझकर अपने एजेंटों के जरिए 1xBet को प्रमोट करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ विज्ञापन कंपनियों के साथ अनुबंध किए थे। ये अनुबंध विदेशी कंपनियों के जरिए किए गए पैमेंट के बदले में किए गए थे,

ताकि फंड के अवैध स्रोत को छिपाया जा सके, जो अवैध बेटिंग गतिविधियों से होने वाले अपराध की कमाई से जुड़े हैं। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि 1xBet भारत में बिना इजाजत के काम कर रहा था और सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट मीडिया के

बेटिंग ऐप केस



रडार पर ये बड़े नाम

सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के मामले की जांच में ईडी द्वारा जो संपत्तियां जब्त की गई हैं, उनमें पूर्व क्रिकेटर्स, फिल्म अभिनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों का नाम सामने आ रहा है। जांच एजेंसी ने इस मामले में कथित वित्तीय लेन-देन का पता लगाया है। जिन व्यक्तियों की संपत्तियां जब्त की गई हैं, उनमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, अंकुश हजरा, रोबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, नेहा शर्मा, तृणमूल कांग्रेस पूर्व सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हाजरा शामिल हैं।

जा नें किसकी कितनी संपत्ति हुई अटैच?

इस मामले में ईडी ने युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपये, रोबिन उथप्पा की 8.26 लाख रुपये, उर्वशी रौतेला की 2.02 करोड़ रुपये (उनकी मां के नाम पर पंजीकृत), सोनू सूद की 1 करोड़ रुपये, मिमी चक्रवर्ती 59 लाख रुपये, अंकुश हजरा 47.20 करोड़ रुपये और नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की गई हैं। यह कार्रवाई गुरुवार को हुई है। ईडी ने पहले भी 1xBet मामले में कई बड़े नामों के खिलाफ कार्रवाई की है। क्रिकेटर शिखर धवन से जुड़ी 4.55 करोड़ रुपये और पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना से जुड़ी 6.64 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई थीं। अब 1xBet मामले में जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 19.07 करोड़ तक पहुंच गया है।

सुप्रीम कोर्ट में 2 जनवरी तक विंटर वेकेशन



जरूरी मामलों में 22 दिसंबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अवकाशकालीन सत्र 22 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मामलों की संख्या देखने के बाद वे तय करेंगे कि कितनी पीठों की बैठक होनी चाहिए। दरअसल, सीजेआई सूर्यकांत ने यह घोषणा तब की है, जब कुछ वकीलों ने मौखिक रूप से कुछ मामलों को आज ही तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। क्योंकि, न्यायालय शीतकालीन अवकाश के लिए बंद हो रहा है। 22 दिसंबर से 2 जनवरी विंटर वेकेशन की छुट्टी रहेगी।

'हम सुनवाई के लिए तैयार हैं...'

एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील ने कोर्ट में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो लोग भी सुनवाई के लिए लाइन में हैं, क्या सोमवार (22 दिसंबर) को बहस करेंगे? हम सोमवार को सुनवाई के लिए तैयार हैं।

कैसे पढ़ेंगे फाइल?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि वे आज किसी भी मामले की सुनवाई की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह बहुत सारे मामले दर्ज हुए हैं और न्यायाधीश पहले से ही फाइलों का अध्ययन करने में व्यस्त हैं। उन्होंने पूछा कि अगर आज मामले सूचीबद्ध किए जाते हैं तो वे फाइलें कैसे पढ़ेंगे।

इस शर्त पर करेंगे सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा कि हम सोमवार को इस शर्त पर सुनवाई करेंगे कि आप बहस करेंगे। आप जहां भी तत्काल ज्ञापन भेजेंगे, हम पता लगाएंगे कि क्या वास्तव में कोई तत्काल आवश्यकता है और उसे सोमवार को सूचीबद्ध करेंगे। बस आपको सोमवार को बहस करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा ने कहा कि माननीय न्यायाधीश पूरी रात फाइलें पढ़ते रहे हैं क्योंकि बहुत सारी फाइलें जमा हुई थीं। उन्होंने अपनी पूरी रात संक्षिप्त विवरण पढ़ने में बिताई है। मैं उनसे आज कोई नया संक्षिप्त विवरण पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। जब बच्चे की हिरासत, जमानत, गिरफ्तारी से सुरक्षा आदि से संबंधित कुछ अन्य मामलों का जिक्र हुआ, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह तुरंत पता लगाया जाएगा कि क्या वास्तव में कोई तात्कालिकता है। यदि यह पाया जाता है कि वास्तव में कोई तात्कालिकता, अंतरिम जमानत या हिरासत का मुद्दा है, तो हम 22 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेंगे।

न्यूज़ ब्रीफ

गर्भवती महिला पर हमला करने के आरोप में एसएचओ निलंबित

कोच्चि। पिछले साल कोच्चि में एक गर्भवती महिला को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के कारण थाना प्रभारी अब निलंबित किया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अलापुझा जिले के अरुण पुलिस स्टेशन के एसएचओ के रूप में कार्यरत प्रताप चंद्रन केजे को 20 जून, 2024 को हुई घटना की सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। पुलिस के अनुसार निरालंभ आदेश दक्षिण जोन के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा राज्य पुलिस प्रमुख रावडा चंद्रशेखर के निर्देशों पर जारी किया गया था। कोच्चि की निवासी श्यामोल एनजे पर कथित तौर पर चंद्रन ने हमला किया था, जो उस समय एनकुलम नॉर्थ पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे। यह घटना तब हुई जब उनके पति बैजो को एक मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में चंद्रन को पुलिस स्टेशन में हुई झड़प के दौरान श्यामोल को धक्का देते और बाद में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही फुटेज में एक महिला पुलिस अधिकारी भी श्यामोल को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है।

बांग्लादेश में हिंसा पर शशि थरुन ने जताई चिंता
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरुन ने बांग्लादेश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यहां हिंसा की वजह से भारत को दो वीजा केंद्र बंद करने पड़े हैं, जो बेहद निराशाजनक है। थरुन के मुताबिक, बांग्लादेश के कई नागरिक पहले ही शिकायत कर रहे थे कि उन्हें भारत के वीजा पहले की तरह आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं, और मौजूदा हालात ने भारत सरकार के लिए उनकी मदद करना और मुश्किल बना दिया है।

सबरीमाला मामले में दो और लोगों की गिरफ्तारी

कोच्चि। सबरीमला सोना चोरी मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दो और लोगों की गिरफ्तारी की है। एसआईटी ने शुक्रवार को स्मार्ट क्रिपशन के सीईओ पंकज भंडारी और गोवर्धन को गिरफ्तार किया। गोवर्धन की कर्नाटक के बेल्लारी में गहनों की दुकान है। केरल पुलिस के डीजीपी रावद चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी। इससे पहले बुधवार को त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस श्रीकुमार को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को सबरीमला सोना चोरी मामले में एसआईटी ने देवरवोम बोर्ड के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस श्रीकुमार को गिरफ्तार किया। वर्ष 2019 में जब मंदिर के द्वार पर मूर्तियों से सोने की परत हटाई गई थी, उस समय श्रीकुमार प्रशासनिक अधिकारी के पद पर थे।

महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी सीबीआई

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश किया रद्द

पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला



नई दिल्ली। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में CBI फिलहाल TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोकपाल की ओर से चार्जशीट फाइल करने की मंजूरी को रद्द कर दिया है। यह मंजूरी 12 नवंबर को दी गई थी। जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा- 'हमारा मानना है कि लोकपाल ने इस मामले में गलती की है।'

कोर्ट ने लोकपाल से कहा है कि वह लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत एक महीने के भीतर कानून के अनुसार दोबारा फैसला करे। सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा के वकील ने दलील दी कि लोकपाल ने मंजूरी देते समय कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया। कानून के मुताबिक किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ मंजूरी देने से पहले उनकी टिप्पणी लेना जरूरी होता है, जो नहीं ली गई।

क्या है मामला?

दरअसल, यह मामला अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था। जब BJP सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेने के बदले में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडाणी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। महुआ पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगा था। इसके बाद यह मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी में भेज दिया गया था, जहां पर महुआ दोषी पाई गई थीं। इसके बाद महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। लोकसभा की एथिक्स कमेटी में महुआ के दोषी पाए जाने के बाद। मामला लोकपाल के पास पहुंचा।

बिक्रम मजीठिया को नहीं मिली राहत

नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी जरूर दी है, लेकिन अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस बिक्रम नाथ और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 19 जनवरी तय की है। मजीठिया ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 4 दिसंबर को अपने आदेश में कहा था कि मजीठिया के बाहर आने पर जांच को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मजीठिया प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति हैं और गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं। हालांकि, हाई कोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था और कहा था कि इसके बाद मजीठिया फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।



तेलंगाना में 41 माओवादी सरेंडर

हैदराबाद। तेलंगाना में प्रतिबंधित CPI (माओवादी) संगठन के 41 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 6 वरिष्ठ कैडर (कंपनी प्लाटून और डिविजनल कमेटी स्तर) शामिल हैं। यह जानकारी DGP वी. शिवधर रेड्डी ने दी। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने हिंसा छोड़ने का ऐलान किया और पुलिस को 24 हथियार सौंपे। इनमें INSAS LMG, AK-47, SLR और 733 जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक नक्सली नेतृत्व से नाराज थे। उन्हें अनजान और दूर इलाकों में जबरन भेजा जा रहा था, जहां रहने, खाने और आवाजाही में भारी दिक्कत थीं। इसी वजह से उन्होंने संगठन छोड़ने का फैसला किया। सरेंडर करने



वाले नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत कुल 1.46 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी। DGP ने बताया कि 2025 में अब तक 509 माओवादी तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। इससे संगठन की ताकत लगातार कमजोर हो रही है। पुलिस ने माओवादी नेतृत्व के उस दावे को भी खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि मार्च 2026 के बाद सुरक्षा अभियान कमजोर पड़ जाएगा।

मतदाता सूची से हटाए गए लाखों नाम

चुनाव आयोग ने जारी की ड्राफ्ट सूची

एजेंसी | चेन्नई

तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्यभर की सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। इसी बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज यानी 19 दिसंबर, शुक्रवार को तमिलनाडु की एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बाद प्रकाशित की गई है, जो पूरे राज्य में चलाया गया था। जिला चुनाव कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, इस प्रक्रिया में कई जिलों से लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसके तहत कोयंबटूर में करीब 6.50 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए। वहीं डिंडीगुल जिले में 2.34 लाख वोटर हटे, जिससे कुल मतदाता संख्या 19.35 लाख से घटकर 16.09 लाख रह गई।



मतदाता सूची से क्यों हटाए गए नाम, समझिए?

चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट सूची से लाखों मतदाताओं का नाम क्यों हटाया गया। इस बात को चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए बयान के आधार पर ऐसे समझा जा सकता है कि सूची में शामिल 1.56 लाख लोगों की मीत हो गई, 27,323 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, 12.22 लाख वोटर दूसरे स्थान पर

चेन्नई में हुई सबसे ज्यादा कटौती

बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा जारी ड्राफ्ट सूची का सबसे ज्यादा असर राजधानी चेन्नई में देखने को मिला। यहां यहां 14.25 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए। इसके बाद कुल मतदाता संख्या 40.04 लाख से घटकर 25.79 लाख रह गई। करूर जिले में 79,690 मतदाताओं के नाम हटाए गए। यहां मतदाता संख्या 8.79 लाख से घटकर 8.18 लाख हो गई। साथ ही कांचीपुरम जिले में 2.74 लाख वोटरों के नाम काटे गए।

सुरक्षा समुद्र में भारत को मिली नई ताकत

तटरक्षक बल में शामिल हुआ जहाज 'अमूल्य'

एजेंसी | नई दिल्ली

भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री ताकत में एक और आधुनिक जहाज जुड़ गया है। नए जमाने के एडवन्स श्रेणी के तीसरे फास्ट पेट्रोल वेसल 'अमूल्य' को शुक्रवार को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया गया। अधिकारियों के अनुसार यह जहाज निगरानी, खोज और बचाव अभियान, तस्कारी रोकने और समुद्री प्रदूषण से निपटने जैसे कई अहम मिशनों को अंजाम देगा। इससे भारत के पूर्वी तट (ईस्ट कोस्ट) की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह जहाज समुद्र को सुरक्षित, साफ और संरक्षित रखने के लिए तटरक्षक बल की मजबूत इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बता दें कि 51 मीटर लंबा यह फास्ट पेट्रोल जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में डिजाइन और तैयार किया गया है। इसमें 60 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इससे रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की सफलता साफ दिखाई देती है।



गौरतलब है कि आईसीजीएस अमूल्य को ओडिशा के पारादीप में तैनात किया जाएगा। यह जहाज तटरक्षक बल के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कमांडर के अधीन काम करेगा। जहाज की

ताकत और रफ्तार से लेस

जानकारी के अनुसार 'अमूल्य' में दो अत्याधुनिक 3000 किलोवाट डीजल इंजन लगे हैं, जिनसे यह जहाज 27 नॉट्स की अधिकतम गति से चल सकता है। यह एक बार में 1500 समुद्री मील तक का सफर तय कर सकता है, जिससे लंबे समय तक समुद्र में मिशन संभव हो पाता है। इसके साथ ही जहाज में 30 मिमी की तोप 12.7 मिमी की दो रिमोट कंट्रोल गन लगाई गई हैं। इसके अलावा, इसमें लक्ष्य पहचान और फायर कंट्रोल के आधुनिक सिस्टम भी हैं। साथ ही, इसमें इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, मशीनरी कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं, जो जहाज की कार्यक्षमता और सुरक्षा को और बेहतर बनाते हैं।

ओडिशा के पारादीप में होगी तैनाती

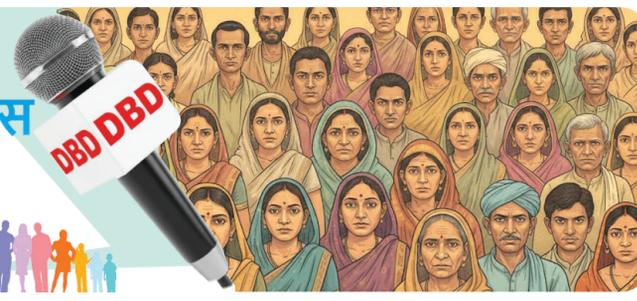
कमान कमांडेंट (जूनियर ग्रेड) अनुपम सिंह के पास है और इसमें 5 अधिकारी और 34 जवान तैनात रहेंगे। मामले में अधिकारियों ने कहा कि 'अमूल्य' के शामिल होने से तटरक्षक बल की

ताकत और बढ़ेगी। यह जहाज तटीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी और आपातकालीन राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाएगा और देश की समुद्री सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित बनाएगा।

मनरेगा कानून को बदलने के विरोध में उत्तरी डीएमके



नई दिल्ली। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस ने मनरेगा के बदले लिए गए नए विधेयक के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का एलान किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कानून के खिलाफ 24 दिसंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मनरेगा योजना के लाभार्थियों को डीएमके और अन्य सहयोगी पार्टियों के जिला सचिवों, विधायकों, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों और गठबंधन पार्टियों के सदस्यों द्वारा लामबंद किया जाएगा। गठबंधन की मांग है कि विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 को वापस लिया जाए, जो मनरेगा को खत्म करता है और एक नया ग्रामीण रोजगार ढांचा पेश करता है। डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जारी बयान में कहा, '24 दिसंबर को, प्रदेश में सुबह 10 बजे और पार्टी के सभी स्थानीय स्तरों पर 100-दिवसीय रोजगार योजना के लाभार्थियों को लामबंद करके विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।'



कोने-कोने से...

पुणे मनपा चुनाव में वंशवाद का मुद्दा गरम

पुणे। महानगर पालिका (मनपा) चुनावों की रणभेरी बजते ही शहर की राजनीति में 'वंशवाद' का मुद्दा गरमा गया है। एक ओर जहां सभी प्रमुख दल 'इलेक्टिव मेरिट' और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने का दावा कर रहे हैं। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में इस मुद्दे पर अधिक चर्चा हो रही है, जहां कथित तौर पर 16 में से 12 दावेदार सीधे तौर पर पार्टी की पुरानी पृष्ठभूमि से जुड़े परिवारों से आते हैं। चुनाव में जिन चेहरों पर सबकी नजर टिकी है, उनमें प्रमुख नाम कुणाल तिलक (दिवंगत विधायक मुक्ता तिलक के पुत्र), स्वरदा बापट (दिवंगत सांसद गिरीश बापट की बहू), राधेवेंद व हर्षवर्धन मानकर (पूर्व उपमहापौर दीपक मानकर के पुत्र), करण मिसाल (विधायक व राज्य मंत्री माधुरी

भाजपा टिकट के लिए 1100 दावेदार मैदान में

छत्रपति संभाजीनगर। छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए प्रतिसाद देखने को मिल रहा है। मनपा चुनाव के लिए भाजपा के पास करीब 1100 इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इनमें से पहले दिन 500 इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार विभागीय कार्यालय में संपन्न हुए। शहराध्यक्ष शितोले ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव निर्णय समिति ने 2 दिवसीय साक्षात्कार कार्यक्रम तय किया है। पहले दिन यानी गुरुवार 18 दिसंबर को दस अलग अलग पैनोंलों द्वारा प्रभाग क्रमांक 1 से 18 तक के 500 इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए गए। दूसरे चरण के साक्षात्कार 19 दिसंबर को आयोजित किए गए। इस चरण में प्रभाग क्रमांक 19 से 29 तक के इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार भाजपा के विभागीय कार्यालय में लिए गए।

मनीष पाटिल दंपति राष्ट्रवादी में

अमरावती। महापालिका चुनाव से पहले नेताओं का इधर से उधर होने का सिलसिला तेज हो गया है। आज यशोदा नगर के बीजेपी नेता मनीष पाटिल और उनकी पत्नी अर्चना पाटिल ने बीजेपी छोड़ राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है। यह जानकारी राकांपा नेता अविनाश माडीकर ने दी और बताया कि विधायक संजय खोडके ने पाटिल और उनके समर्थकों का राष्ट्रवादी में घड़ी का दुपट्टा डालकर स्वागत किया। बता दें कि राष्ट्रवादी में गुरुवार को ही सिराज खान और सचिन निगम ने धूमधडाके से प्रवेश किया था। जिससे माना जा रहा है कि विधायक संजय खोडके मनपा चुनाव को लेकर बड़े गुरु गंभीर हैं और सभी 87 स्थानों पर चुनाव लड़ने के लिए तगड़े उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रहे हैं। मनीष पाटिल यशोदा नगर भाग में दबदबा रखते हैं।

जेन जी

जो भी जीते, हमारी बस्ती में नियमित सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करे, यही हमारी मांग है।
- महेंद्र परमार, विरार

पिछले कुछ वर्षों में अनियोजित विकास से नागरिक सुविधाएं दब में आई हैं। इस बार हम उसी उम्मीदवार और पार्टी को वोट देंगे जो समयबद्ध काम, जवाबदेही और स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ शहर के विकास का ठोस रोडमैप पेश करे।
- मनीषा तिवारी, विरार

हमें भेजें

अगर आप भी अपने विचार हमें भेजना चाहते हैं तो **8356804318** इस नंबर पर व्हाट्सप्य करें।

विश्लेषण

दादागिरी की भाईगिरी

अमित बज्र | नवी मुंबई
महानगरपालिका चुनाव की घोषणा के साथ ही नवी मुंबई में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) मिलकर चुनाव लड़ेंगे या पुणे मनपा की तर्ज पर 'फ्रेंडली फाइट' होगी। इस अनिश्चितता के कारण कार्यकर्ताओं और इच्छुक उम्मीदवारों में भारी असमंजस बना हुआ है। ठाणे जिले की अन्य महानगरपालिकाओं में गठबंधन के संकेत मिल चुके हैं, लेकिन नवी मुंबई को लेकर तत्पर अब भी धुंधली है। दिल्ली नेतृत्व की ओर से ठाणे जिले की सभी महानगरपालिकाओं में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के निर्देश दिए गए हैं। यदि यह आदेश नवी मुंबई पर भी लागू होता है, तो भाजपा के कद्दावर नेता और वन मंत्री गणेश नाईक को शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के साथ समझौता करना पड़ सकता है। यह स्थिति नाईक समर्थकों के लिए सहज नहीं है, क्योंकि नवी मुंबई में दोनों दलों के बीच लंबे समय से सीधी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है। वहीं शिंदे समूह गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। इसलिए, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 21 तारीख को अकेले चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। अतः, नवी मुंबई में भाई बनाम दादा जैसी टक्कर होने की प्रबल संभावना है। भाजपा और शिवसेना, जो महागठबंधन में हैं, इस बार आमने-सामने नजर आएंगी।



गणेश नाईक का मजबूत गढ़

नवी मुंबई को गणेश नाईक का अभेद गढ़ माना जाता है। 111 सीटों वाली नवी मुंबई महानगरपालिका में 15 जनवरी को चुनाव प्रस्तावित हैं। मनपा की स्थापना के बाद से नाईक का शहर की सत्ता पर गहरा प्रभाव रहा है। 2014 में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद, 2015 के मनपा चुनाव में उन्होंने एनसीपी को सत्ता दिलाकर यह साबित किया कि मोदी लहर के दौर में भी नवी मुंबई की जनता उनके साथ खड़ी रही। 2019 में गणेश नाईक के भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए। उनके साथ बड़ी संख्या में नगरसेवक भी भाजपा में आए और पहली बार भाजपा नवी मुंबई मनपा की सत्ता तक पहुंची। वर्तमान में भाजपा के साथ 60 से अधिक पुराने नगरसेवक हैं। नाईक और उनका परिवार इस चुनाव को अपने दम पर लड़ने के पक्षधर हैं, लेकिन गठबंधन का दबाव उनकी रणनीति को प्रभावित कर सकता है।

कुल 9,48,460 मतदाता

नवी मुंबई महानगरपालिका चुनाव में कुल 111 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसके लिए शहर को 28 वार्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से 27 वार्डों से चार-चार सदस्य चुने जाएंगे, जबकि एक वार्ड से तीन सदस्य निर्वाचित होंगे। इस चुनाव में कुल 9,48,460 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिनमें 5,16,267 पुरुष, 4,32,040 महिला और 153 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए 1,141 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 6,275 चुनाव कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।

पार्टी नेताओं का मत

शिंदे सेना के विजय नाहटा ने कहा कि पार्टी नवी मुंबई में मजबूत संगठन के साथ हर वार्ड में चुनाव लड़ेंगी और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देशानुसार कार्य करेगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी अपने नेतृत्व द्वारा निर्धारित दिशा का पालन करते हुए पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगी। एनसीपी (अजीत पवार गुट) का कहना है कि गठबंधन का फैसला वरिष्ठ स्तर पर होगा और सभी क्षेत्रों के पेशेवरों को अधिकतम अवसर प्रदान किए जाएंगे। वन मंत्री गणेश नाईक ने दावा किया कि नवी मुंबई का अगला महापौर भाजपा से ही होगा, जो पार्टी की नगर निकाय पर वर्चस्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।

शिवसेना (शिंदे गुट) की ताकत और संभावित टकराव

शिंदे गुट की शिवसेना के पास भी नवी मुंबई में 45 से अधिक पुराने नगरसेवक हैं। यदि गठबंधन नहीं होता, तो भाजपा और शिवसेना के बीच सीधी और कड़ी टक्कर तय मानी जा रही है। ऐरोली और बेलापुर विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक होने के बावजूद, शिवसेना का सांगठनिक आधार मजबूत है। यही वजह है कि दोनों दलों की सीधी लड़ाई शहर की राजनीति को और अधिक रोचक बना सकती है।

गठबंधन का गणित और भाजपा की दुविधा

यदि भाजपा-शिवसेना गठबंधन होता है, तो भाजपा को शिवसेना को कम से कम 45 सीटें देनी पड़ेंगी, जिससे नाईक समर्थकों के लिए कई वार्डों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। भाजपा द्वारा शुरू किए गए इंटरव्यू प्रोसेस में भी कई इच्छुक उम्मीदवारों ने गठबंधन के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई है। ऐसे में नवी मुंबई मनपा चुनाव भाजपा के लिए केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि संगठनात्मक संतुलन और नेतृत्व की परीक्षा भी बनता नजर आ रहा है।

2015 में चुने गए 111 पार्षदों में से 105 ने चुनाव आयोग को पूर्ण हलफनामे प्रस्तुत किए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स (एडीआर) और महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच के विश्लेषण के अनुसार, 69 पार्षद करोड़पति थे। पार्षदों द्वारा घोषित संपत्ति का औसत मूल्य 4.54 करोड़ रुपये था। इनमें से 14 पार्षदों ने 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बताई, जिससे नगर निकाय में वित्तीय दबदबे का संकेत मिलता है। एनसीपी की नेत्र शिरके ने 40.30 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। शिवसेना के किशोर पाटकर 37.92 करोड़ रुपये और नामदेव भगत 30.47 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भाजपा के रूपचंद बंधु संयुक्त मोर्चे के रूप में उतर सकते हैं। इस संभावित गठबंधन की रणनीति का केंद्र 'MaMu' फेक्टर माना जा रहा है। 'MaMu' का अर्थ है मराठी-मुस्लिम समीकरण। मुंबई की राजनीति में यह सामाजिक संतुलन लंबे समय से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। योजना के तहत मराठी बहुल इलाकों के साथ-साथ मुस्लिम प्रभाव वाले वार्डों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा, ताकि दोनों समुदायों का संयुक्त समर्थन हासिल किया जा सके।

मानखुर्द-शिवाजी नगर

बचेगा या दरकेगा सपा का गढ़!

धीरज सिंह | मुंबई
महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव की घोषणा के साथ ही मानखुर्द-शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर राजनीतिक दलों के लिए सबसे अहम रणक्षेत्र बनकर उभरा है। प्रभाग आरक्षण और मतदाता सूची सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सियासी दलों ने रणनीति तेज कर दी है। बीते करीब दो दशकों से इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में समाजवादी पार्टी (सपा) का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) सपा के गढ़ में सीधी संघ लगाने की स्थिति में नजर आ रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव के वॉर्डवार आंकड़े बताते हैं कि कुछ प्रभागों में AIMIM ने मजबूत पकड़ बना ली है, जिससे आगामी मनपा चुनाव का गणित बदल सकता है।



सपा को झटका, संगठन में दरार

मनपा चुनाव से ठीक पहले सपा को बड़ा झटका तब लगा, जब दो पूर्व नगरसेवक आयशा रफीक शेख और अख्तर कुरेशी ने पार्टी छोड़कर शिवसेना (शिंदे गुट) का दामन थाम लिया। इन्हीं नगरसेवकों के दम पर विधायक अबू आसिम आजमी लंबे समय से इस सीट पर जीत दर्ज करते आए हैं। मानखुर्द-शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में मुंबई मनपा के कुल 9 प्रभाग (134 से 142) आते हैं। 2017 के मनपा चुनाव में सपा ने यहां 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना (अविभाजित) को 2, राकांपा (अविभाजित) को 1 और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी।

बदला महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य

पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति में हुए बड़े उलटफेर का असर इस क्षेत्र में भी साफ दिखाई देता है। मौजूदा 9 पूर्व नगरसेवकों में से चार अब शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ हैं, जिनमें दो सपा से, एक राकांपा (शरद गुट) से और एक शिवसेना (उद्धव गुट) से जुड़े रहे नेता शामिल हैं। इसी दौरान AIMIM ने भी जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत किया है, जिसका असर 2024 के विधानसभा चुनाव में साफ नजर आया। 2024 के विधानसभा चुनाव में AIMIM प्रत्याशी अलीक शेख को 42,027 वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे, जबकि सपा उम्मीदवार व मौजूदा विधायक अबू आसिम आजमी को 54,780 वोटों से संतोष करना पड़ा। यह आंकड़ा 2019 के मुकाबले काफी कम है, जब आजमी को 69,082 वोट मिले थे। विशेषज्ञों के अनुसार यह गिरावट मुस्लिम मतों के विभाजन का संकेत है, जिससे सपा की बढ़त को कमजोर किया।

वॉर्डवार ताकत का समीकरण

मानखुर्द-शिवाजी नगर में करीब 58 प्रतिशत मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं, जबकि 42 प्रतिशत अन्य समुदायों से आते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव चुनाव में प्रभाग 134 और 136 में AIMIM का दबदबा दिखा, वहीं प्रभाग 135, 141 और 142 में महायुति मजबूत स्थिति में रही। दूसरी ओर प्रभाग 137, 138, 139 और 140 में सपा का वर्चस्व कायम रहा। यही वॉर्डवार बंटवारा आगामी मनपा चुनाव की दिशा तय कर सकता है।

कांटे का मुकाबला तय

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि मनपा चुनाव में भी मुस्लिम मतों का इसी तरह विभाजन हुआ, तो इसका सीधा फायदा AIMIM और महायुति को मिल सकता है, जबकि सपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

पिछले चुनाव में कौन जीता ?

- वॉर्ड 134 : समाजवादी पार्टी की सायरा खान ने इस वार्ड से जीत हासिल की थी। उस समय उन्होंने शिवसेना की उम्मीदवार वर्षा मोहिते को हराया था।
- वॉर्ड 135 : शिवसेना के समिक्षा साखरे ने 2,804 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी।
- वॉर्ड 136 : समाजवादी पार्टी की रुखसाना नजीम सिद्दीकी 6,364 वोटों के साथ विजयी रहीं।
- वॉर्ड 137 : समाजवादी पार्टी की आयेशा रफीक शेख ने 8,343 वोट हासिल किए और जीत दर्ज की।
- वॉर्ड 138 : समाजवादी पार्टी की आयशा खान 6,110 वोटों के साथ विजयी रहीं।
- वॉर्ड 139 : समाजवादी पार्टी के अख्तर अब्दुलराज्जक कुरेशी 4,782 वोटों के साथ जीत गए।
- वॉर्ड 140 : राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस पार्टी (NCP) की नादिया मोहसिन शेख 4,673 वोटों के साथ विजयी रहीं।
- वॉर्ड 141 : कांग्रेस के विठ्ठल गोविंद लोकरे 3,642 वोटों के साथ जीते थे।
- वॉर्ड 142 : शिवसेना की वैशाली नाविन शेवाले ने 5,312 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी।

आंकड़ों में इलेक्शन

MaMu फेक्टर से बीएमसी फतह की तैयारी

मुंबई की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव की ओर बढ़ती दिख रही है। करीब एक दशक की राजनीतिक दूरी के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के लिए साथ आने की तैयारी में हैं। शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के बीच चल रही बातचीत से संकेत मिल रहे हैं कि आगामी बीएमसी चुनाव में ठाकरे बंधु संयुक्त मोर्चे के रूप में उतर सकते हैं। इस संभावित गठबंधन की रणनीति का केंद्र 'MaMu' फेक्टर माना जा रहा है। 'MaMu' का अर्थ है मराठी-मुस्लिम समीकरण। मुंबई की राजनीति में यह सामाजिक संतुलन लंबे समय से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। योजना के तहत मराठी बहुल इलाकों के साथ-साथ मुस्लिम प्रभाव वाले वार्डों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा, ताकि दोनों समुदायों का संयुक्त समर्थन हासिल किया जा सके।

MaMu फेक्टर का गणित

मुंबई के 72 मराठी बहुल और 41 मुस्लिम प्रभाव वाले वार्ड चुनाव की दिशा तय करेंगे। यदि गठबंधन इन 113 निर्णायक वार्डों में 55-60% सीटें भी निकाल लेता है, तो अकेले इसी सामाजिक समीकरण से 60-65 सीटें हासिल हो सकती हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में इसी पैटर्न ने यूबीटी को शहरी मुस्लिम इलाकों में बढ़त दिलाई थी।

वोट कटाव बनाम वोट ट्रांसफर

गठबंधन का सबसे बड़ा फायदा वोट कटाव रोकना होगा। 2017 में मराठी वोटों का बड़ा हिस्सा एमएनएस-शिवसेना में बंट गया था, जिससे भाजपा को फायदा हुआ। इस बार मराठी वोटों का एकीकरण होने पर भाजपा का वोट प्रतिशत कई वार्डों में 5-8% तक घट सकता है, जो हार-जीत का अंतर बन सकता है।

सीट शेयरिंग की चुनौती

सीट शेयरिंग का सबसे कठिन हिस्सा वल्लो, दादर-माहिम, सिवरी और विक्रोली-भांडुप जैसे मराठी गढ़ हैं। यदि यहां टकराव हुआ तो गठबंधन का औसत स्ट्राइक रेट 15-20 सीटों तक घट सकता है। साफ और संतुलित सीट बंटवारा ही इस गठबंधन की चुनावी सफलता की कुंजी होगा।

संभावित अंतिम तस्वीर

- यूबीटी-एमएनएस गठबंधन: 95-120 सीटें
- महायुति: 85-105 सीटें
- अन्य/निर्दलीय: 10-20 सीटें